● वर्ष-2
● अंक-283
रायपुर, बुधवार 19 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

अब एनडीए करेगा इंडिया का मुकाबला

विपक्षी गठबंधन का नया नाम हुआ तय, चार बिंदुओं पर बनी सहमति

नईदिल्ली। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के महागठबंधन को नया नाम मिल गया है। इसे अब इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के नाम से जाना जाएगा। हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन नाम दिया गया है। 26 दलों के नेता इस नाम पर सहमति बना चुके हैं और बेंगलुरु बैठक में चार अहम मुद्दों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। अमर उजाला को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विपक्षी दलों की इस बैठक में यूपीए की तर्ज पर राज्यवार गठबंधन, सीट बंटवारे समेत महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा हुई है। बैठक में सभी दलों के साथ समन्वय और तालमेल के लिए एक संयोजक बनाने पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी के नाम पर किसी भी दल को कोई एतराज नहीं होगा। क्योंकि वे पीएम पद की दावेदार भी नहीं होंगी। हालांकि अगर इस पद को लेकर कोई विवाद उठेगा तो कांग्रेस इससे पीछे भी हट सकती है।

इन चार बिंदुओं पर फैसला

सूत्रों के मुताबिक, इस दूसरी अहम बैठक में कांग्रेस चाहती है कि यूपीए की तर्ज पर सभी विपक्षी पार्टियों की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हों। क्योंकि वह सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की नेता हैं और पीएम पद की वे दावेदार नहीं हैं। हालांकि पटना की बैठक में कुछ दलों के नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात रखी थी। अगर अधिकांश दल नीतीश के नाम पर राजी होते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान लेगी।सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुर में कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम विपक्षी गठबंधन होगा, बल्कि इसे मोदी बनाम जनता का रूप दे दिया जाए। इसके लिए मौजूदा मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जाए।

इसमें युवा, किसान, महिला और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया जाएगा।

विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में एकता और समन्वय स्थापित करने के लिए एक संयोजक भी बनाया जाए। इसके अलावा चुनावों में राज्यवार कौन से मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना है, केंद्र सरकार को कैसे घेरना है जैसे सभी मुद्दों को तय करने के लिए अलग से नेताओं का एक समूह (ग्रुप) बनाया जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी इस तरह फैसला होगा। इसके अलावा राज्यों में नेताओं से बात करने के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि एक ग्रुप और बनाया जा सकता है, जो ये तय करेगा कि किन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है या संसद के सत्र में सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बने साथ ही सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होना चाहिए।

इंडिया हो सकता है विपक्षी मोर्चा का नाम

बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर भी मुहर लगी। कांग्रेस नेता माणिक टैगोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जीतेगा इंडिया। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट में लिखा है चक दे इंडिया।

नाम बदलने से कुछ नहीं होता : सुशील मोदी

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। इसके बाद इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब भाजपा

की ओर से इसका जवाब दिया गया है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भाजपा नेता ने अपने बयान में कहा कि भारत का मतलब है यहां की संस्कृति, सभ्यता, यहां के गरीब व गांव में रहने वाले लोग। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुछ लोग इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह लड़ाई वर्षों से चली आ रही है, भारत की ही जीत होगी क्योंकि ह्ल्ल भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश को लगा था कि उन्हें संजोयक या विपक्ष का चेहरा घोषित किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसलिए वे चले गए। वे चार्टर प्लेन से आए थे अगर 2 घंटे बाद भी निकलते तो कुछ नहीं होता। उन्हें वहां शायद वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे जिसके चलते वे और लालू यादव वहां से निकल गए।

नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई : राहुल गांधी

बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज बहुत ही सार्थक बैठक

हुई है जिसमें बहुत काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी फैल रही है। चुने हुए लोगों के हाथ में पूरा धन जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। राहुल ने कहा कि हमारी लड़ाई इस देश के लिए है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं है।

इन दिनों

कांग्रेस की कुर्बानी मजबूरी या बड़प्पन?

2024 चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त है। ऐसे में इसको लेकर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वर्तमान में देखें तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव एनडीए बनाम विपक्षी एकता रहने वाला है जिससे इंडिया का नाम दिया जा रहा है। आज की बेंगलुरु की बैठक से कई बड़े संदेश भी निकले हैं। इस बैठक पर पूरे देश की नजर थी। बैठक में 26 दलों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के राजनीति साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। आज की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कांग्रेस की कुर्बानी के चर्चे हो रहे हैं। विपक्ष की बैठक में खरगे ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और पार्टी नेता पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य दौड़ लगा रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। खड़के के बयान से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस ने पहले ही प्रधानमंत्री पद से अपनी दावेदारी छोड़ दी है? इसे कांग्रेस की कुर्बानी भी समझी जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने यह कुर्बानी दी या फिर आत्मसमर्पण किया? राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भविष्य को देखते हुए कांग्रेस की ओर से यह राजनीतिक सौदेबाजी है। कांग्रेस फिलहाल विपक्षी दलों को अपने भरोसे में रखना चाहती है। कांग्रेस यह नहीं चाहती कि 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता में किसी भी तरह का रोड़ा उत्पन्न हो। कांग्रेस को अच्छे से पता है कि मिल बैठकर बात कर लेने भर से ही सारे मसले का हल नहीं निकलेगा, गठबंधन की असली परीक्षा सीट बंटवारे को लेकर होगी। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को मैदान खाली कर देना चाहिए। भविष्य में सीटों के बंटवारे में अड़चन ना आए इसलिए अभी से ही कांग्रेस ने अपना नरम रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस को यह बात अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से डील नरम रुख के आधार पर ही हो सकता है। तेवर रखने पर मामला बिगड़ सकता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। सभी राज्यों में इसकी मौजूदगी है। ऐसे में कांग्रेस को यह लगता है कि अगर वह सबसे ज्यादा सीट जीत जाती है तो प्रधानमंत्री पद उसके पास से कहीं और नहीं जाएगा। यही कारण है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर कांग्रेस थोड़ा नाम रख रही है। कांग्रेस ने अभी से ही यह कुर्बानी इसलिए भी देनी शुरू कर दी है ताकि क्षेत्रीय दल भी जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के लिए कुर्बानी दे सकें।

रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव कार्य समिति की बैठक में भाग लेने विधानसभा परिसर स्थित समित कक्ष की ओर जाते हुए।

विस का मानसून सत्र शुरू, दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। विधानसभा सदस्यों ने दिवंगत नेताओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा और फिर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र 21 जुलाई को समाप्त होगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सत्र के प्रारंभ में वैशाली नगर (भिलाई) विधानसभा से विधायक रहे स्वर्गीय विद्या रतन भसीन तथा अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित सदन के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वर्गीय श्री भसीन सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर हमेशा आमजन के कल्याण के लिए कार्य किया। श्री भसीन का जनहित से गहरा सरोकार था। वे लगातार क्षेत्र की समस्याएं और प्रदेश के प्रमुख मुद्दे

विधानसभा में उठाते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय भानुप्रताप सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय भानुप्रताप सिंह स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह के छोटे भाई थे। स्वर्गीय भानुप्रताप सिंह ने कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को भी श्रद्धांजलि दी। चांडी का मंगलवार को निधन हो गया। श्रद्धांजलि के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने भसीन और सिंह के निधन का उल्लेख किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मंत्री मोहन मरकाम समेत अन्य सदस्यों ने दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। विधानसभा सदस्यों ने दिवंगत नेताओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा और फिर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र 21 जुलाई को समाप्त होगा।

प्रमुख समाचार

राहुल-सोनिया गांधी की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग

भोपाल । कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट की भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते भोपाल में लैंड की गई। दोनों नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेता नॉन शेड्यूल फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब 8 बजे तकनीकी खराबी की चलते उनकी फ्लाइट भोपाल में लैंड हुई। इसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंचे। इसमें विधायक कुणाल चौधरी, आरिफ मसूद, पीसी शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, शोभा ओझा ने राहुल और सोनिया से मुलाकात की। दोनों नेता भोपाल से इंडिगो की फ्लाइट से करीब 9.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले बेंगलुरु में मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में 26 विपक्षी दल एक साथ शामिल हुए। इस दौरान यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (क्क) का नाम बदलकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (ढ्ढहृष्ठढ्ढ) रखा गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के नए नाम का औपचारिक एलान किया।

द्रमुक नेता को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को द्रमुक नेता आरएस भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ दायर की थी। भारती ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान कई करोड़ रुपये के राजमार्ग निविदा में अनियमितता हुई। अदालत ने द्रमुक के संगठन सचिव भारती को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें सतर्कता विभाग को मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने भारती की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 2021 में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार नए सिरे से प्रारंभिक जांच का कोई कारण नहीं है। भारती की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 2018 में मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया। जब उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए लिया, तो राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में नए सिरे से जांच की जाएगी।

कांग्रेस के नेता ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे

नई दिल्ली । ओडिशा में कांग्रेस के निलंबित नेता एवं पूर्व विधायक चिरंजीब बिस्वाल ने दावा किया है कि वह ''कुछ ऐसे लोगों के समूह की साजिश का शिकार हुए हैं जिन्होंने कभी कोई

चुनाव नहीं जीता''। बिस्वाल और बाराबती-कटक से विधायक मोहम्मद मोकिम को हाल में ''पार्टी विरोधी गतिविधियों'' के आरोप में कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री बसंत बिस्वाल के पुत्र चिरंजीब बिस्वाल ने कहा, ''मैं कांग्रेस परिवार से हूं। मैंने और मेरे भाई (आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद रंजीब बिस्वाल) ने हमेशा ओडिशा में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया है।'' बीजू जनता दल (बीजद) की मजबूत लहर के बावजूद 2004 और 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले बिस्वाल ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, ''कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में कभी कोई चुनाव नहीं जीता। '' उन्होंने दावा किया कि जगतसिंहपुर जिले के लोग उनके साथ हैं।

वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने हिंसा रोकने की अपील की

नई दिल्ली । मणिपुर में बीते तीन महीनों से दंगे हो रहे है। मणिपुर की जनता पर इन दंगों और हिंसा का काफी असर देखने को मिला है। इस हिंसा को लेकर अब ओलंपिक पदक विजेता वेटलिफ्टर

मीराबाई चानू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में शांति स्थापित करने की अपील की है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के हालातों को खत्म करने की अपील की है। गौरतलब है कि मणिपुर में मई महीने की शुरुआत से ही मैतेई और कुकी जातीय समुदायों के बीच संघर्ष जाती है, जिस कारण राज्य में उथल पुथल हो गई है। मणिपुर की इस हिंसा में अबतक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कई घरों को भी आग के हवाले किया गया है। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर में चल रही लड़ाई को तीन महीने होने वाला है, अब तक शांति बहाल नहीं हो पाई है।

पहले इश्क अब सीमा गुलाम हैदर का एटीएस से सामना

नई दिल्ली । इन दिनों पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की प्रेम कहानी सुर्खियों में है। दोनों के बीच क्क्रक्चत्र खेलते वक्त इश्क हुआ। ये इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई फिर नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंच गईं। इसी महीने की चार तारीख को सचिन और उनके पिता नेत्रपाल के साथ सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद भी सीमा समेत अन्य की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पूछताछ कर रहा है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो सिंध प्रांत की निवासी हैं। 27 वर्षीय सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा अपनी पहली शादी के बाद पति गुलाम हैदर के साथ कराची में रह रहीं थीं। उनका दावा है कि उनके पति ने उन्हें फोन पर तलाक दे दिया था और अब वो संपर्क में नहीं है। जानकारी के मुताबिक, सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करते हैं। सीमा फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के सचिन मीणा के साथ रह रहीं हैं। सीमा ने इस साल की शुरुआत में अपनी दूसरी शादी सचिन के साथ नेपाल के काठमांडू में की थी और हिंदू धर्म अपना लिया था।

विश्लेषण

छोटे सियासी दलों के लिए अस्तित्व का संकट

राजेश बादल

क्षेत्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के लिए वर्तमान कालखंड बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को विचारधारा के साथ बचाए रखना उनके लिए आसान नहीं रहा है। वैचारिक आधार पर तो वे पहले ही सूखे का सामना कर रहे थे। अब बढ़ती महत्वाकांक्षा और सियासी चालों ने जिस तरह इन दलों में टूट-फूट को बढ़ावा दिया है, वह सोचने को बाध्य करता है कि भारतीय संविधान में संरक्षण प्राप्त बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली कितने दिन चलेगी और क्या इसमें केवल बड़ी पार्टियों के लिए संभावना शेष रहती है ?

आपको याद होगा कि आजादी के बाद भारत में जो राजनीतिक दल पनपे, वे किसी न किसी ठोस वैचारिक धुरी पर टिके हुए थे। कांग्रेस का अपने आप में एक संपूर्ण भारतीय आधार था। उसके पास स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत विरासत थी और महात्मा गांधी, नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस (भले ही वे कम समय रहे), सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे महत्वपूर्ण राजनेता उसके पास थे। दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मधु दंडवते, मधु लिमये, मामा बालेश्वर दयाल सियासी परिदृश्य पर छाए हुए थे। दक्षिणपंथी विचार की नुमाइंदगी करने वाला जनसंघ था। उसके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और लालकृष्ण आडवाणी जैसे चमकदार चेहरे थे। वामपंथी धारा से ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त और भूपेश गुप्त जैसे कद्दावर लोग थे। इन राजनेताओं ने

कभी अपने सरोकारों को नहीं छोड़ा और हमेशा सकारात्मक राजनीति के जरिये देशसेवा करते रहे। अस्सी के दशक तक हम लोगों ने ऐसी सियासत देखी। अपवाद स्वरूप कुछ झटके लोकतंत्र को अवश्य लगे, पर उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आपातकाल का दौर ऐसा ही था। लेकिन नब्बे का दशक राजनीतिक अस्थिरता लाया और अनेक क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक दलों ने आकार लिया। तब से आज तक इन दलों की संख्या बढ़ती ही रही है। यह अलग बात है कि इन प्रादेशिक पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं भी विकराल रूप लेती रहीं। उनकी पूर्ति के लिए वे विचारों की धुरी से भटक गईं। उनके लिए अपने वोट बैंक को बनाए रखना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने जाति, उप जाति, धर्म, धन और बाहुबल का सहारा लिया। यह भारतीय लोकतंत्र का अंधकार युग कहा जा सकता है। यह ठीक है कि किसी भी जम्हूरियत में आप सियासी पार्टियों के विकास को नहीं रोक सकते, मगर वे अपने सोच के आधार को छोड़ दें तो यह प्रजातांत्रिक सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा।

इन हालात के मद्देनजर वर्तमान दशक क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक पार्टियों के लिए अशुभ माना जा सकता है। देश की राजनीति दो वैचारिक खेमों में बंट गई है और छोटे दलों के लिए किसी एक खेमे से अपने को जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है। इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। मुश्किल तो तब होती है, जब बड़ी पार्टियां छोटे दलों का साथ तो लेती हैं, लेकिन बाद में वे उनके हितों पर ही प्रहार करने लग जाती हैं। वे कोशिश करती हैं कि मंझोले दल भी बिखर जाएं। इसके लिए वे कई बार अपने सहयोगी दलों की दूसरी पंक्ति के नेताओं का शिकार करने लगती हैं, जो महत्वाकांक्षी हों, पार्टी में पर्याप्त सम्मान तथा स्थान नहीं मिलने से दुःखी हों या फिर सियासत करने के लिए पैसे की खातिर बिक जाएं।

हालांकि प्रादेशिक पार्टियों का अपना आंतरिक संगठन ढांचा भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। उनमें वर्षों तक संगठन चुनाव नहीं होते, एक परिवार या एक गुट का वर्चस्व बना रहता है और दूसरी तीसरी कतार के नेता अवसर मिलने के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं। एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता तथा राजनेता कब तक अपनी तड़प के साथ इंतजार करेगा ? जब उसका धीरज साथ छोड़ देगा तो वह पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। बीते दिनों एक नेता ने कहा कि भविष्य में भारत की सारी क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। वैसे तो इस तरह की सोच ही संवैधानिक लोकतंत्र के नजरिये से जायज नहीं है। आप किसी को भी राजनीति में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकते। स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिन इन दलों के लिए चुनौती भरे हैं। चाहे वह तेलुगु देशम हो या बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी हो अथवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना हो या तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी हो अथवा जनता दल यूनाइटेड।

नक्सलियों के डिप्टी कमांडर ने किया सरेंडर

■ एसपी सहित 45 जवानों की हत्या में रहा शामिल

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के डिप्टी कमांडर सन्नू मंडावी ने मंगलवार को बीएसएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर तीन लाख रुपये का इनाम था। वह मदनवाड़ा में हुए एसपी हत्याकांड सहित 45 जवानों की शहादत में शामिल रहा था। सन्नू मंडावी परतापुर इलाके में सक्रिय था और अपने साथ इंसास व एसएलआर रायफल रखकर चलता था। सरेंडर के बाद सन्नू मंडावी ने बताया कि वह नक्सली संगठन में काफी परेशान हो गया था। इसके बाद उसे छोड़कर घर आ गया। वहां उसके साथी परेशान करने लगे तो तंग आकर सरेंडर कर दिया।

हिंसा और प्रताड़ना से तंग आकर छोड़ा नक्सल रास्ता

सन्नू मंडावी नक्सली संगठन के मिलिट्री प्लाटून नंबर 5 के सेक्शन ए का डिप्टी कमांडर था। उसने बताया कि 2005 में सलवा जुडूम के दौरान उसके घर में आग लगा दी गई थी। इसके चलते वह भागकर परिवार के साथ जंगल में चला गया। वहां उसके पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में नक्सली उसे ले गए और खाना दिया। इसके बाद उसे संगठन में भर्ती कर लिया और ट्रेनिंग दी गई। वह कई वारदातों में शामिल रहा। हालांकि जंगल में उसे फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

लगातार नक्सली उसका शोषण और अत्याचार करते। फिर हिंसा से तंग आकर उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

नक्सली संगठन बाल संघम में हुआ था भर्ती

अंतागढ़ एडिशनल एसपी खोमन सिन्हा ने बताया कि नक्सली सन्नू मंडावी उर्फ शिवाजी वर्ष 2005 में बाल संघम के रूप में भर्ती हुआ था। फिर वर्ष 2005-06 में तीन माह कंपनी नंबर- दो में रहा। वर्ष 2006 में पदोन्नत होकर उत्तर बस्तर डिवीजन के अंतर्गत सक्रिय परतापुर एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर- 05 में सेक्शन डिप्टी कमांडर के रूप वर्ष 2016 तक कार्य करता रहा। सन्नू मंडावी ने 2015 में नक्सल संगठन में ही रहते हुए जीतो जुर्री से शादी कर ली थी। इसके चलते उसे संगठन में डिमोट कर दिया गया। वर्ष 2016 में उसे गंगालूर एरिया कमेटी भेजा गया और मनकेली जनमिलिशिया कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी।

सन्नु माड़वी इन वारदातों में रहा शामिल

2006 : एनएमडीसी हिरोली दंतेवाड़ा में 8 सीआईएसएफ जवानों की हत्या कर 17 हथियार लूटे।

2007: विश्रामपुरी पुलिस थाना, जिला कोण्डागांव में हमला कर एक सहायक उप निरीक्षक, दो प्रधान आरक्षक की हत्या की में शामिल था।

2009 : मदनवाड़ा कैम्प हमला, जिसमें एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवानों का हत्या की गई। इस एम्बुश में 300 माओवादी सुधाकर और रामेदर के नेतृत्व में शामिल रहा।

2010 में थाना दुर्गुकोंदल थाना के भुस्की गांव में बीएसएएफ के पांच जवानों की हत्याकर हथियार लूट में शामिल था।

2019 में गोरना गांव, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट किया। इसमें डीआरजी के जवान घायल हुए।

2023 में जनमिलिशिया कमांडर के रूप में मनकेली (बीजापुर) पंचायत एरिया में कैम्प के विरोध में पेड़ काटकर रोड़ ब्लाक कर नक्सल बैनर पोस्टर लगाए।

20 लाख के इनामी दो नक्सली दंपत्तियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 20 लाख के इनामी दो नक्सली दंपत्तियों पीएलजीए बटालियन नंबर 01 के छोटू मंडावी व उसकी पत्नि लखमे टेक्निकल टीम सदस्य एवं पीएलजीए मिलिट्री प्लाटून नंबर 31 का सदस्य नक्सली कमांडर कोसा व उसकी पत्नि आयते मिडियामी ने दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित दोनो दंपत्ति ग्राम एर्रापल्ली से लेकर मिनपा, गलगम एवं एलमागुण्डा सहित कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है।

पुलिस मिली जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सली आयते मिडियामी गादीरास के कोर्रा निवासी, वर्तमान में वह 26 वर्ष की है। वर्ष 2007 से नक्सल संगठन में काम कर रही है। यानी इस समय आयते की उम्र महज 10 वर्ष की थी। पढ़ने-लिखने, खेलने कूदने की उम्र में नक्सली अपने साथ ले गए थे। वर्ष 2012 तक चेतना नाट्य मंडली की सदस्य थी, 15 वर्ष की उम्र में हथियार चलाना सिखाया, कई मुठभेड़ों में शामिल रही। आयते मिडियामी 12 बोर की बंदूक अपने साथ रखती थी। संगठन में रहते हुए नक्सली कमांडर कोसा से प्रेम हुआ, दोनों ने शादी कर ली। अब पति के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। उसका पति और आत्मसमर्पित नक्सली कोसा सुकमा जिले के गच्चनपल्ली का निवासी है। वर्ष 2000 से यह नक्सल संगठन से जुड़कर काम कर रहा, वर्तमान में 39 वर्ष का है, कोसा 16 वर्ष की उम्र में ही संगठन में शामिल हो गया था, 23 वर्ष तक संगठन से जुड़ा रहा। कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा। संगठन में रहते आयते से इसने शादी की थी। आत्मसमर्पित नक्सली छोटू मंडावी डुमरीपालनार का निवासी है। वर्तमान में इसकी उम्र 25 वर्ष है, 15 वर्ष की उम्र में ही नक्सलवाद से जुड़ गया। वर्तमान में नक्सलियों की टेक्निकल टीम का कमांडर था। हथियार मरम्मत का काम करता था। संगठन में रहते इसने टेक्निकल टीम सदस्य लखमे से शादी कर ली। आत्मसमर्पित लखमे की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष है। इसने 02 वर्ष पहले यानी 16 वर्ष की उम्र में नक्सलवाद का दामन थामा था। अब इन दोनो दंपतियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

प्रदेश की संस्कृति और परम्परा को सहेजने का काम कर रही हैं सरकार : जायसवाल

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम तिहार हरेली का पर्व कोरबा जिले में धूमधाम से मनाया गया। कटघोरा ब्लॉक के ग्राम बुंदेली गौठान ग्राम पंचायत कसईपाली में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां छत्तीसगढ़ महतारी, कृषि उपकरणों के साथ गाय की पूजा अर्चना की गई। यहां हरेली त्योहार मनाने के साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 का भी जिले में शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ विधायक व संचालक सीजीएमएससी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफकिया, देश में सबसे ज्यादा मूल्य में धान खरीदने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को लाभान्वित करने का भी काम किया। यही नहीं छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है, जहां गोबर खरीदी की जा रही है और खाद का निर्माण कर स्व-स्हायता समूह की महिलाओं को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हर जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें गांव के गरीब विद्यार्थी भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य की संस्कृति, परम्पराओं को सहेजने और पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हरेली जैसे पर्व का आयोजन हो या छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन, सभी से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को देश-दुनिया में एक नई पहचान मिल रही है।

मुख्य अतिथि डॉ. जायसवाल ने आगे कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जैसी योजनाओं ने गरीबों के विकास के रास्ते खोले हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ

स्वाभिमान से जीना सिखाया है। हजारों गौठान का निर्माण कर नवाचार से ग्रामीण आजीविका पार्क और रोजगार की नई संभावनाएं विकसित की गई है। मितानिन, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जनपद सदस्य सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित कर गरीबों का कल्याण किया गया है। उन्होंने हरेली पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कटघोरा विधायक श्री पुरूषोत्तम कंवर ने कहा कि हरेली पर्व का सरकारी स्तर पर आयोजन बहुत ही गर्व की बात है। इससे हमारी संस्कृति और परम्परा को एक नई पहचान मिल रही है। आज ही छत्तीसगढ़ी ओलम्पिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, इससे ग्रामीण प्रतिभाएं सामने आएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लगातार यहां की परम्परा और संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी में स्वागत उदबोधन देते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से छत्तीसगढ़ी संस्कृति, मान्यता, विश्वास, आस्था और पुरखों का मान सम्मान बढ़ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट

■ फिल्म के पोस्टर पर एडिट कर लगाए चेहरे

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में एक मूवी के पोस्टर में एडिट कर सीएम भूपेश और एक पूर्व अफसर की फोटो लगाई गई है। साथ ही उस पर अभ्रद कमेंट भी किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करने वाले आरोपी के खिलाफ कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, व्हाट्सएप ग्रुप मरवाही जनादेश पर रात करीब 8.30 बजे एक पोस्ट की गई। इसमें मूवी तू झूठी मैं मक्कार का पोस्टर था। हालांकि इसमें बने एक्टर और एक्ट्रेस की फोटो को एडिट कर उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक पूर्व अफसर की फोटो लगाई गई। साथ ही इस पर अभद्र कमेंट भी किया गया था। ग्रुप में फोटो शेयर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखी तो वो भड़क

गए। उन्होंने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। वह पूरे प्रदेश का होता हैं। इस तरह से उनकी फोटो में छेड़खानी कर अभद्र टिप्पणी करने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए हम लोग थाने आए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ग्रुप में भेजे गए मैसेज को लेकर साइबर सेल की मदद से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

अमगांव के प्रभावित ग्रामीणों ने नापी सर्वे का किया विरोध

कोरबा। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के द्वारा ग्राम अमगांव को खनन कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया है पहले अमगांव के मुख्य बस्ती को दो हिस्से में परिसंपत्तियों का नापी सर्वे किया गया था लेकिन नापी सर्वे उपरांत मुआवजा रोजगार बसाहट समेत अन्य मामले आज भी लंबित पड़े हैं जिसके कारण ग्राम पंचायत अमगांव के प्रभावित ग्रामीणों के द्वारा लगातार नापी सर्वे का विरोध किया जा रहा है पहले लंबित पड़े प्रकरणों की सुनवाई करने के बाद ही नापी सर्वे का कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत अनगांव के शेष बचे परिसंपत्तियों को एसईसीएल गेवरा प्रबंधन नापी सर्वे करने के लिए अमादा है जिसका अमगांव पंचायत के प्रभावित ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है प्रभावित ग्रामीणों ने सर्वे टीम को वहां से चलता कर दिया प्रभावितों ने कहा कि पहले लंबित पड़े मुआवजा रोजगार बसाहट सहित अन्य मामले की निराकरण किया जाना चाहिए वे सर्वे को रोक लगाने के लिए पाली एसडीएम से मांग करेंगे ।

ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति संगठन ने ग्राम पंचायत अमगांव पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों के साथ नापी सर्वे को बंद करा कर वापस लौटाये

संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा कि प्रभावित ग्रामीणों के द्वारा अपने लंबित पड़े मुआवजा रोजगार बसाहट सहित अन्य मामले का निराकरण की मांग कर रहे हैं इसके बाद भी एसईसीएल प्रबंधन लगातार नापी सर्वे करने के लिए अमादा है बरसात का समय भी है और इस समय किसान अपनी फसल बुवाई खेती किसानी में उलझा रहता है घर पर पुरुष महिला वर्ग नहीं रहते वे खेती किसानी के कामों में व्यस्त रहते हैं और ऐसे समय में एसईसीएल गेवरा प्रबंधन के द्वारा लगातार नापी सर्वे का दबाव बनाया जा रहा है जिसका जबरदस्त प्रभावित ग्रामीणों के साथ सर्वे टीम का विरोध किया गया और वहां से वापस जाने को कहा गया कुलदीप आगे कहा कि इस मामले को लेकर पाली विकासखंड के अनुविभागीय दंडाधिकारी को लंबित पड़े अमगांव पंचायत के मुआवजा रोजगार बसाहट सहित अन्य मामले का निराकरण करने के लिए मांग किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एमडी के बैठक से बिजली समस्या का हल नहीं निकला

कोरबा। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि कोरबा के विधायक व राजस्व मंत्री द्वारा एमडी को पत्र लिखकर कोरबा में लचर बिजली व्यवस्था से निजात पाने के लिए स्थाई व्यवस्था की मांग की थी तदुपरांत मंत्री के कहे अनुसार एमडी ने बैठक लिया जिसमें महापौर और मंत्री बिजली यूनियन भी शामिल हुए लेकिन जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं बुलाया गया एमडी ने अपने बैठक के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने बाद वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 33 केवी लाइन में एक साइड की बिजली गुल होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिसमें 1 महीने का समय लगेगा अगर स्थाई व्यवस्था की जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था ही करनी थी तो गर्मी के आगमन से पूर्व क्यों नहीं किया गया वैकल्पिक व्यवस्था जब तक होगी कब तक आमजन व व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिन्हा ने आगे बताया कि कोरबा जिला उर्जा धानी के रूप में जाना जाता है यहां से पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के कोने कोने में बिजली की आपूर्ति की जाती है।

पेंशनरों ने महंगाई राहत देने लगाई गुहार

कवर्धा। सरकार पेंशनरों को महंगाई राहत दे ज्ञात हो कि पूरे देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, केंद्र शासन द्वारा अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को विगत 1 जनवरी से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि की गई है, परंतु खेद है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा 9वा महंगाई राहत की घोषणा नही की गई है। इस परिपेक्ष में दिनांक 14 जुलाई को सीनियर सिनियर समिति कवर्धा के समस्त सदस्यों ने एक बैठक आयोजित कर शासन के इस रवैया के प्रति आक्रोश व्यक्त किया एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को प्रेषित कर शीघ्र ही 1 जनवरी से केंद्र शासन द्वारा घोषित महंगाई राहत प्रदान करने की मांग समिति के अध्यक्ष मदन तंबोली , सचिव चंद्रहास राजपूत,पूर्व अध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत व्याख्याता आदित्य श्रीवास्तव, डॉक्टर एन के यदु, प्रदेश प्रतिनिधि इंजीनियर एसएस जैन एवं अन्य सदस्यों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र ही महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है।

सामान्य सभा एवं महासभा की बैठक हुई

कोरबा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा सामान्य सभा, महासमिति की बैठक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों व नवनियुक्त जिला अध्यक्षका सम्मान कार्यक्रम राजधानी रायपुर के कलेक्टर स्थित रेड क्रास सोसाइटी भवन में आयोजित की गई। जिसमें पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव माननीय श्री विकास उपाध्याय, फेडरेशन प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, मुख्य संरक्षक पी.आर. यादव, संरक्षक अजय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष जी.आर चंद्रा एवं वरिष्ठ पदाधिकारी व विशिष्ट अतिथि के रूप मे मंच पर उपस्थित रहे जिला शाखा कोरबा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जे पी उपाध्याय श्री सुंदर सिंह एवं नव नियुक्त जिलाध्यक्ष श्री नकुल रजवाड़े का सम्मान किया गया। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 01 अगस्त से होने वालेअनिश्चित कालीन आंदोलन मे जाने हेतु विस्तार पूर्व अपनी बात रखा।

चतुर्थ श्रेणी पद के लिए कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग में निकली भर्ती

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का फिर से नया मौका आया है। वर्तमान में कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों (वाटरमैन, चौकीदार, फर्राश, माली, स्वीपर) के पदों पर अर्हता प्राप्त नागरिकों से आवेदन मंगाया गया है। इन पदों के लिए 31.07.2023 के प्रात: 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / स्कूल से कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लंबर अन्य कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी / संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यदि प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने कॉलोनी में किया पौधरोपण

रायगढ़। नगर के वृंदावन कॉलोनी में, रामदास द्रौपदी फाउंडेशन द्वारा कॉलोनी वासियों के प्रस्ताव के कारण, हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन में योगदान देने वाले कॉलोनी के लोगों को स्थानीय महिला मण्डल द्वारा सम्मानित भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 के कैबिनेट सेक्रेटरी लायन दयानंद अवस्थी ने स्थानीय निवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के विषय पर लोगों से अपनी अनुभव साझा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ही रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील रामदास के संदेश को भी लोगों से साझा की। जिसमें उन्होंने कहा कि रामदास द्रौपदी फाउंडेशन द्वारा यह अभियान हमारे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने और पर्यावरण को मानवीय जीवन के अनुकूल बनाने के लिए चलाया जा रहा है।

एसडीएम के ट्रांसफर पर कांग्रेसियों का जश्न

■ दफ्तर में छिड़का गंगाजल, नए अफसर को दिया उपहार

मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संयुक्त कलेक्टर और खंड़गवां की एसडीएम नयन तारा सिंह तोमर के ट्रांसफर पर कांग्रेसियों ने मंगलवार को जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेसी गंगाजल लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां छिड़का। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद कांग्रेसी कार्यालय में गंगाजल छिड़कने में कामयाब रहे। कार्यकर्ताओं ने जकर नारेबाजी और आतिशबाजी की। वहीं नए एसडीएम का स्वागत किया।

दरअसल, कांग्रेसियों ने अपनी ही सरकार की महिला अफसर और मनेंद्रगढ़

की एसडीएम नयन तारा सिंह तोमर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साथ ही उनके ट्रांसफर की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। शासन की ओर से प्रदेश में भर में किए गए अफसरों के तबादले की लिस्ट में एसडीएम नयन तारा का भी नाम है। इसके बाद कांग्रेसी खुश हो गए और बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। गंगाजल लेकर पहुंचे कांग्रेसी आफिस का शुद्धिकरण करने की बात कह रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं से उनकी जमकर नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों में जमकर बहस होती रही। इसके बाद कांग्रेसी परिसर के अंदर गेट तक पहुंच गए और वहां गंगाजल छिड़का। इसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही परिसर में आतिशबाजी भी की। इस दौरान नव नियुक्त एसडीएम विजेंद्र सारथी भी वहां पहुंच गए। कांग्रेसियों ने उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो भेंट की और कार्यालय गेट पर ही बैठकर भतन कीर्तन किया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि, खंड़गंवा की एसडीएम नयन तारा सिंह तोमर के खिलाफ कई शिकायतें हैं। उनकी शिकायत के बाद उनका ट्रांसफर किया गया है। गंगाजल से एसडीएम कार्यालय को पवित्र किया गया है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में सभी के कार्य समय पर पूर्ण हो। किसी को कोई तकलीफ न हो। सरकार की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में कोई अफसर भ्रष्टाचार करेगा, लोगों के हित में काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनते हैं।

सत्या पावर के संचालकों के यहां आईटी की दबिश

■ रेलवे ठेकेदार सुशील झांझरिया के निवास भी पहुंची है टीम

बिलासपुर। केंद्रीय आयकर की टीम ने मंगलवार की सुबह हंसा विहार स्थित सत्या पावर के रामावतार अग्रवाल व पवन अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी। दोनों उद्योगपतियों के ठिकाने के अलावा टिकरापारा में रेलवे ठेकेदार के ठिकानों पर भी कारवाई चल रही है।केंद्रीय आयकर की टीम टिकरापारा स्थित रेलवे के बड़े ठेकेदार के घर भी पहुंची है। रेलवे ठेकेदार सुशील झांझरिया के टिकरापारा स्थित निवास पर ही उनका कार्यालय है, यहां भी जांच जारी है।

मंगलवार की सुबह पांच बजे करीब दो दर्जन से अधिक केंद्रीय आयकर की टीम करीब 25 गाडियों के साथ हंसा विहार कालोनी पहुंची। आयकर की टीम की एक ब्रांच ने एक साथ हंसा विहार स्थित उद्योगपति राम अवतार अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल और पवन अग्रवाल के निवास, कार्यालय और रतनपुर मार्ग स्थित सत्या पावर फैक्ट्री को निशाना

बनाया।

टीम इस समय जगह जगह बन्द कमरे में युद्ध स्तर पर छानबीन कर रही है। आयकर की टीम टिकरापारा स्थित रेलवे ठेकेदार के घर को भी निशाना बनाया है। रेलवे ठेकेदार सुशील झांझरिया पर आय से अधिक सम्पत्ति, मनी लांडरिंग समेत टैक्स चोरी का आरोप है। सुशील झांझरिया की गिनती देश के नामचीन रेलवे ठेकेदारों में होती है। जब टीम ने हंसा विहार स्थित उद्योगपतियों के ठिकानों पर धावा बोला, ठीक उसी समय आधा दर्जन से अधिक टीम के कर्मचारियों ने झांझरिया को भी निशाने पर लिया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक

नयी दिल्ली। संसद के गुरुवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जायेगी। संसदीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की पूर्वसंध्या पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक अपराह्न 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

एनडीए में शामिल होते ही नीतीश पर बरसे चिराग

पटना। सोमवार को चिराग पासवान एनडीए में अधिकृत रूप से शामिल हो गए। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ 2025 में बिना नीतीश कुमार के एनडीए सरकार बनाएगी। चिराग ने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे, उस गठबंधन को नुकसान ही होगा। नीतीश कुमार के प्रति जो जनता का आक्रोश है। वह 2020 में भी हमने देखा जब उनके आधे से अधिक उम्मीदवार हार गए और जदयू तीसरे नंबर की पार्टी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बिहार में महागठबंधन बना है। जनता को यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की 40 से 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी।

थरूर ने मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए मोदी की तारीफ की

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की इस्लामिक देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते इस्लामिक देशों से बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा, विदेश नीति को लेकर मैं मोदी शासन का आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुझे याद है कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, जिसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। कांग्रेस सांसद रहते हुए मैंने यह मुद्दा उठाया भी था, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अब जो उन्होंने इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए किया है, वह शानदार है। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। बड़े मुस्लिम देशों से हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं थे। मैं खुशी से अपनी पुरानी आलोचना को वापस लेता हूं।

राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 को करेगा सुनवाई

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की। यह अपील 15 जुलाई को दायर की गई थी, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद उच्च न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुनर्जीवित करने के प्रयास को झटका देते हुए फैसला सुनाया था कि कांग्रेस नेता ने विनम्रता का उल्लंघन किया और उनके अपराध में नैतिक अधमता शामिल थी। अपनी अपील में गांधी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि उनकी दोषसिद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए।

विपक्ष की बैठक का एजेंडा सिर्फ मोदी को हटानाः अठावले

नईदिल्ली। 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। बेंगलुरु में जहां विपक्षी दलों की बैठक हुई वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 350 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी बैठक पर भी निशाना साधा और कहा कि यह केवल सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर है। अपने बयान में रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष की बैठक का एजेंडा जनता का कल्याण नहीं बल्कि पीएम मोदी को हटाना है। विपक्ष की बैठक में लगभग 26 दलों ने भाग लिया है, लेकिन एनडीए में हमारे पास लगभग 38 दलों के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा देश के विकास के साथ-साथ नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना है। हम 2024 का लोकसभा चुनाव 350 से अधिक सीटों के साथ जीतेंगे।

बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला

भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, उनका मंत्र है – परिवार का, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेता बेंगलुरु में मंगलवार को बैठक हुई। मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 के लिए देश के लोगों ने हमारी सरकार वापस लाने का मन बना लिया है। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हें देखकर मुझे एक अवधी कविता याद आती है, गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है। जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। 24 के लिए 26 होने वाले दलों पर ये फिट बैठता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने न केवल पुरानी सरकारों की गलतियों को सुधारा है, बल्कि लोगों को नई सुविधाएं और रास्ते भी दिए हैं। भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। यह सबका साथ, सबका विकास का मॉडल है।

विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो इनके परिवार का भला हो, नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र और द्वीप हैं वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही।

बंगाल में सरेआम हिंसा हुई, पर ये जो जमात इकट्ठा, सबकी बोलती बंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान विपक्षी एकता पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष की एक ही विचारधारा और एजेंडा है 'अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ'।

पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज वाले इलाकों तक नहीं पहुंचा सका। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे, जिसमें इनका खुद का भला हो इनके परिवार का भला हो, नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र और द्वीप हैं वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। उन्होंने वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के नौ वर्षों की तुलना भी की। कहा कि पिछले नौ वर्षों में हमने न केवल पुरानी सरकारों की गलतियों को सुधारा है, बल्कि लोगों को नई सुविधाएं और रास्ते भी दिए हैं। भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। यह सबका साथ, सबका विकास का मॉडल है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे से पहले की सरकार के नौ साल में अंडमान निकोबार को करीब 23,000 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया गया था। जबकि हमारी सरकार के दौरान अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब 48 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वहीं, पिछली सरकार में अंडमान निकोबार में करीब 28 हजार घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया था। हमारी सरकार में यहां के करीब 50 हजार घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 2018 में मैंने अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा लहराया जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था। ये हमारी ही सरकार है जिसने रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष का नाम दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने हेवलॉक और नील आइलैंड को स्वराज और शहीद आइलैंड का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं ये ही कहना चाहूंगा कि नफरत है घोटाले हैं, तुष्टीकरण है मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। इनके लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने बच्चों और भाई-भतीजों का विकास मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा और एजेंडा है – अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम मोदी ने कहा कि ये जो जमात इकट्ठी हुई है, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग चुप हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून-खराबा हो रहा है, इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में वहां अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है।

हमारा इरादा संविधान की रक्षा करनाः खड़गे

बेंगलुरु। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बेंगलुरू में मंथन कर रहीं विपक्षी पार्टियां एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत हो सकती है। इस बात के संकेत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीटिंग के दौरान दिये हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस इस बैठक की मेजबानी कर रही है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से उस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने बैठक के दौरान यह माना कि महाजुटान में शामिल पार्टियों में राज्य स्तर पर कुछ मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि हममें से कुछ लोगों के बीच मतभेद हैं, लेकिन ये मतभेद वैचारिक नहीं हैं।

विपक्ष के महाजुटान में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महागठबंधन के दलों के बीच ये मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि हम आम आदमी, मध्यम वर्ग, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए इन्हें किनारे नहीं रख सकते। जबकि हम सब इस बात के वाकिफ है कि इनके अधिकारों को हनन हो रहा है और उनकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है।

बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस दो दिवसीय बैठक में हम यहां 26 पार्टियां एकजुट हुए हैं। हम सब की कुल 11 राज्यों में सरकार में है। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिलीं। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आते ही उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन अब जबकि चुनाव नजदीक आ गया है तो बीजेपी अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग-दौड़ कर रहे हैं और बैठक में इन दलों को बुला रहे हैं।

सरकार पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज हर सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाकर किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे नेताओं पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराये जा रहे हैं। हमारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, ताकि उनके खिलाफ आवाज बुलंद ना हो। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदने की बात आम हो गयी है। भाजपा की सरकार और उनके नेता हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर हैं।

विपक्ष की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैंने एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में कहा था कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद का कोई लोभ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बस देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। हमारी लड़ाई संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। महागठबंधन की बैठक को लेकर विपक्ष कह रहा है कि इस बार की बैठक में बीजेपी को सत्ताच्युत करने का पूरा रोडमैप तैयार हो जायेगा। यहां तक कि नेतृत्व को लेकर भी सत्तापक्ष की ओर से जो सवाल किये जा रहे हैं उनके जवाब में महागठबंधन कर रहा है कि वो कोई मसला ही नहीं है और ना ही विवाद। इन हालात में मल्लिकार्जुन खरगे का यह बयान बहुत ही खास है क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहा है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है और वे पीएम पद को लेकर सहमति नहीं बना पायेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने सिंक्लेयर को टीम में जगह दी

त्रिनिदाद। वेस्टइंडीज ने गुरुवार से यहां भारत के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर केविन सिंक्लेयर को बल्लेबाजी ऑलराउंडर रेमन रीफर की जगह टीम में शामिल किया है।

वेस्टइंडीज के लिए सात एकदिवसीय और छह टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले सिंक्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का इंतजार है। डोमिनिका में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी के अंतर से हार के बाद वेस्टइंडीज ने सिंक्लेयर को रीफर की जगह शामिल करके टीम में एकमात्र बदलाव किया है। रीफर हालांकि चोटिल खिलाड़ी के कवर के रूप में टीम के साथ रहेंगे।

सिंक्लेयर इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में वेस्टइंडीज ए के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। वह जिंबाब्वे में आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर के लिए भी वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा थे। यह देखना होगा कि पहले टेस्ट में स्पिन की अनुकूल पिच के बाद वेस्टइंडीज दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए किस तरह की पिच तैयार करता है।

रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट में स्पिन का जादू चलाते हुए मैच में 12 विकेट चटकाए जबकि रविंद्र जडेजा ने पांच विकेट हासिल किए जिससे मैच तीन दिन के भीतर खत्म हो गया। यह मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच 100वां टेस्ट भी होगा। दूसरा और अंतिम टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में गुरुवार (20 जुलाई) से शुरू होगा।

दूसरे टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की टीम- क्रेग ब्रेथवेट (कप्तान), जर्मेन ब्लैकवुड, एलिक अथानाजे, तेजनारायण चंद्रपॉल, रहकीम कोर्नवाल, जोशुआ डा सिल्वा, शेनन गैब्रियल, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, किर्क मैकेंजी, केविन सिंक्लेयर, केमर रोच और जोमेल वारिकन।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 205 अंक उछला निफ्टी 19750 के करीब

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में रिकॉर्ड बढ़त के बाद हालांकि मुनाफावसूली देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद यह 205 अंकों की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। मंगलवार को सेंसेक्स 205.21 (0.31 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 66,795.14 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 37.80 (0.19 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 19,749.25 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दोनों ही इंडेक्स पहली बार इन स्तरों पर बंद हुए हैं। सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान आईटी सेक्टर के शेयरों ने बाजार में दम दिखाया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बैंकिंग सेक्टर में बंपर खरीदारी दिखी जिससे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा पर उसके बाद बाजार में मुनाफावसूली देखी गई।

2000 करोड़ जुटाने के लिए फेडरल बैंक बेचेगी हिस्सेदारी

नईदिल्ली। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए लोन बांटने वाली बैंक की तरफ से बड़ी खबर है। फेडरल बैंक की सब्सिडियरी कंपनी फेडबैंक फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड अपना आईपीओ लाने जा रही है। फेडरल बैंक 2000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपनी गैर बैंकिंग फाइनैंशियल कंपनी फेडफिना में हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रही है। फेडरल बैंक ने बताया कि फेडफिना के निदेशक मंडल ने बैठक में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश लाने का प्रस्ताव रखा है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ में फेडरल बैंक और निजी इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ के नए शेयर और मौजूदा शेयर शामिल हो सकते हैं, जो कंपनी के लगभग एक-चौथाई हिस्से के मालिक हैं। बैंक के सीईओ श्रीनिवासन ने कहा कि फेडरल बैंक, जिसकी फेडफिना में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसमें मेजॉरिटी शेयरहोल्डर बना रहेगा।

ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंफोसिस कर रही जमकर खर्च

नईदिल्ली। टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी (इंफोसिस) ने ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑटोमेशन डेवलपमेंट के लिए अपने मौजूदा स्ट्रेटेजिक ग्राहकों में से एक के साथ समझौता किया है। कंपनी ने बताया कि इसमें कई तरह के समझौते शामिल हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन और मेंटिनेंस सर्विसेज। इंफोसिस ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की तरफ से जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से अगले पांच वर्षों में इसका कुल ग्राहक खर्च लगभग 2 अरब डॉलर आने की उम्मीद है। हालांकि इंफोसिस ने ग्राहक या समझौते पर अधिक जानकारी साझा नहीं की क्योंकि वह 20 जुलाई को अपनी पहली तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट यानी तिमाही रिजल्ट जारी करेगी। भारत में आईटी सर्विस कंपनियां एआई की तरफ ज्यादा दिलचस्पी ले रही है।

निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी अंबानी की कंपनी

नईदिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के निवेशकों के लिए 20 जुलाई का दिन काफी खास दिन रहने वाला है। इस दिन आरआईएल के फाइनैंशियल सर्विस बिजनेस 'रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड' (आरएसआईएल) को अलग यानी इसका डीमर्जर किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि डीमर्जर के बाद मुकेश अंबानी का का सिक्का फाइनैंशियल सर्विस इंडस्ट्री में जम जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वह देश का पांचवा सबसे बड़ा प्राइवेट फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के बेहद करीब हैं। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आरआईएल की फाइनैंशियल सर्विस बिजनेस 'आरएसआईएल' के डीमर्जर की वजह से स्टॉक एक्सचेंज 20 जुलाई को आरआईएल के लिए एक विशेष प्री-ओपन सत्र आयोजित करेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की राह पर भारतीय रुपया

डॉ पीएस वोहरा

इन दिनों इस बात की चर्चा है कि भारत रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। ऐसे कयास भी लगाये जा रहे हैं कि अगर रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित होता है, तो भारत को बहुत आर्थिक लाभ होंगे तथा आने वाले समय में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष एक औपचारिक चर्चा में भारत के केंद्रीय बैंक के यह कहने से हुई कि विश्व के सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अपनी पसंद की मुद्रा के उपयोग का अधिकार होना चाहिए। फिर, ब्रिक्स मुल्कों के सम्मेलन में जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के विकेंद्रीकरण के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण का मुद्दा उठाया, तो इन कयासों को और बल मिला कि संभवत: मोदी सरकार रुपये को भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उपयोग का मन बना रही है। भारत ने एक और पहल करते हुए श्रीलंका जैसे कई छोटे मुल्कों के साथ गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मुद्रा को आपसी लेनदेन का आधार बनाया।

इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक ने अपने नागरिकों को एक विशेष तरह की बैंकिंग सुविधा देनी भी शुरू की, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की डॉलर में निकासी न होकर उस विशेष बैंकिंग खाता (वोस्ट्रो अकाउंट) से भारतीय रुपये में करनी शुरू कर दी। क्या यह इस बात की भी शुरुआत है कि अब डॉलर का वैश्विक दबदबा कम होना शुरू हो गया है? इसके विश्लेषण से निकले तथ्य इस बात का समर्थन करते हैं कि डॉलर के वैश्विक दबदबे के विरुद्ध विश्व के कई मुल्कों में अब एक राय बनती दिख रही है। आइएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 1999 में वैश्विक मुद्रा संग्रहण में

अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी से अधिक थी, जो 2022 में घट कर 59 फीसदी रह गयी। इस गिरावट के पीछे जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां भी जिम्मेदार हैं, जो अनावश्यक रूप से उसकी बादशाहत को विश्व के दूसरे मुल्कों पर थोपती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां रूस और चीन ने मिल कर अमेरिकन डॉलर के विरुद्ध चीनी मुद्रा युआन को बड़ी मजबूती से अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभारा है।

वर्ष 2023 के पहले तीन महीनों में चीन ने अकेले 58 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। रूस भी पिछली तिमाही में 32 मीट्रिक टन सोना खरीद चुका है। वर्ष 2010 के बाद आज विश्वभर में सोने का संग्रह अपने अधिकतम स्तर पर है। इससे पहले विश्व में सोने की अधिकतम खरीदारी 2007 की अमेरिकी मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एकाएक बढ़ी थी। हालांकि, भारत ने सोने की खरीदारी में इतनी हड़बड़ाहट नहीं दिखायी है तथा औसतन प्रति तिमाही 10 मीट्रिक टन सोना ही खरीदा है।

आइएमएफ की ताजा रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2028 तक तकरीबन छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान जताया गया है, पर आर्थिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। इसमें मुख्य बाधा डॉलर में आयातों का भुगतान किया जाना है, जो रुपये के विरुद्ध बहुत महंगा पड़ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने कच्चे तेल को जब रूस से खरीदा और रूस के साथ पारस्परिक लेनदेन रुपये में करने पर सहमति बनायी, तो यह रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने की तरफ भारत की एक कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इसे अभी पूर्ण सफलता इसलिए नहीं माना जा सकता ,क्योंकि रूस डॉलर में भुगतान से मिलने वाले लाभ को भारत से अधिक मात्रा में कच्चा तेल बेच कर वसूलना चाहता है। इसलिए यह भविष्य ही बतायेगा कि कच्चे तेल की अधिक खरीद का भुगतान रुपये में लाभ देगा या नहीं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के रुपये में भुगतान के लिए यदि कुछ विकसित देशों के साथ भारत के पारस्परिक गठजोड़ होते हैं, तो यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता होगी।

एकता की परख होगी सीटों के बँटवारे के समय

नीरज कुमार दुबे

आपने 2018 में बेंगलुरु से आई वह तस्वीर देखी होगी जिसमें तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले संकल्प ले रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन माने जाने वाले कई दल साथ भी आ गये थे लेकिन चुनाव का नतीजा यह आया कि भाजपा 2014 में जीती 282 लोकसभा सीटों के मुकाबले अकेले दम पर 303 सीटें जीत लाई। अब 2018 की तरह 2023 में भी लगभग वही विपक्षी चेहरे एक बार फिर बेंगलुरु में एकत्रित हो रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। विपक्ष की यह कवायद रंग लायेगी या एक बार फिर सत्ता में मोदी की सरकार ही आयेगी यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन विपक्ष सत्ता में आने और सत्तापक्ष पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत कर आने के दावे करने लगा है। अब जबकि लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम का समय बचा है तब भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने मुख्य मुकाबले के लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है। बेंगलुरु में विपक्षी दल एकत्रित होकर भाजपा को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहे हैं तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल एकत्रित हो रहे हैं ताकि एक बार फिर मोदी सरकार की जीत के लिए चुनाव अभियान की रूपरेखा बनाई जा सके। देखा जाये तो मुख्य मुकाबले के लिए तैयारियां दोनों ओर से भरपूर की जा रही हैं। दोनों ओर से सबसे ज्यादा डोरे छोटी पार्टियों पर डाले जा रहे हैं। छोटी पार्टियों को पता है कि केंद्र की राजनीति में भाजपा या कांग्रेस के छाते के नीचे खड़े होकर ही बचा जा सकता है। इसलिए छोटी पार्टियां वंचितों और शोषितों की आवाज उठाने के नाम पर और संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार एनडीए या यूपीए के मंच पर बैठ रही हैं। वैसे विपक्ष के पास इस बार नये चेहरे के रूप में नीतिश कुमार और उद्धव ठाकरे तो हैं ही साथ ही वह अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस के साथ लाने में सफल रहा है। यही नहीं, केरल में एक दूसरे की दुश्मन और बंगाल में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और वामदलों के साथ सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी मंच पर मौजूद है। हालांकि केसीआर, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और नवीन पटनायक जैसे बड़े चेहरे इस महामंच से बाहर हैं। इसके अलावा, हाल ही में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद इस गठबंधन की शक्ति भले कमजोर हुई है लेकिन नेताओं का जोश देखकर लगता नहीं कि उन्हें कोई झटका लगा है। बहरहाल, पटना के बाद अब बेंगलुरु बैठक में भाग लेने के लिए आये सभी विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए जिस तरह एकता की कसमें खाई हैं उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी असली परीक्षा तब होगी जब सीटों के बंटवारे का समय आयेगा।

लौट आया गठबंधन की राजनीति का दौर

अनिल तिवारी

मोदी सरकार के दसवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही मानों अगली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने की संभावना धुंधली होने लगी है। यही कारण है कि एक ओर जहां विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में इकट्ठा होने का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले नरेन्द्र मोदी की ओर से भी एनडीए के पुनर्जीवन के प्रयास शुरु हो गये हैं। 18 जुलाई को दिल्ली से दूर बंगलूरु में 26 विपक्षी दल जहां मोदी को हराने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं वहीं दिल्ली में एनडीए के तहत 38 दलों को इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा है।

संयोग से यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब गठबंधन की राजनीति का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। आज से ठीक 25 साल पहले 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस (एनडीए) नामक राजनीतिक मोर्चे का गठन हुआ था। इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। बाबरी विध्वंस के बाद राजनीतिक रूप से लगभग अछूत बना दी गई भाजपा को इससे न सिर्फ संजीवनी मिली बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले अटल जी के नेतृत्व में देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया।

वास्तव में गठबंधन की राजनीति का ध्येय सर्वसमावेशी है। यह बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की ओर बढ़ने का माध्यम है। लेकिन गठबंधन की राजनीति के अंतर्विरोध भी खूब हैं। गठबंधन में शामिल छोटे-छोटे दलों के नेता व्यक्तिगत स्वार्थों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन का नेतृत्व करने वाले दल पर दबाव बनाकर अपने निजी हितों की पूर्ति करना चाहते हैं।

राजनीतिक विविधताओं से भरे भारत में गठबंधन की सरकारें हकीकत भी हैं और फसाना भी। शायद इसीलिए आजादी के बाद से ही मिली जुली सरकारों को देश के लिए अभिशाप बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने कांटे से कांटा निकालने की तर्ज पर वर्ष 2004 में यूपीए गठबंधन को अमलीजामा पहनाया और गठबंधन के बूते लगातार 10 साल तक रायसीना हिल्स पर राज किया। लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बाद छोटे दलों की अहमियत वह नहीं रही जो 90 के दशक में थी। पिछले 9 वर्षों में विपक्षी एकता की

तमाम कोशिशें हुई पर नतीजा सिफर ही रहा। अब जबकि 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर गठबंधन पर सबका जोर है।

पिछले दिनों पटना में बैठ चुके 15 विपक्षी दल चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए बंगलुरु में फिर से बैठे हैं। वहीं स्पष्ट बहुमत के गुमान में छोटे सहयोगी दलों की अनदेखी के आरोपों से घिरे सत्ताधारी दल के कर्ता-धर्ता भी विपक्षी एकता के बरक्स राज्यों के छोटे-छोटे दलों को मिलाकर अपने गठबंधन का आकार बड़ा करने में दिन-रात जुटे हुए हैं। यानी कि 25 साल पहले जहां से गठबंधन की राजनीति चली थी, एक बार फिर उसी मोड़ पर आ पहुंची हैं। जहां तक देश में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन कर चुनावी मोर्चा तैयार करने की बात है तो यह आजादी के बाद से ही विभिन्न स्वरूप में सामने आता रहा है।

सदन के भीतर विपक्षी दलों के गठबंधन की बात पहली लोकसभा 1952 के गठन के साथ ही शुरू हो गई थी। कुल 499 सदस्यों वाली संसद में कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत हासिल की थी। सत्ता पक्ष के विरुद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ, हिंदू महासभा, अकाली दल, गणतंत्र परिषद को एक साथ लाने में सफल रहे और सदन में इनकी संख्या 32 तक पहुंच गई थी। उसी दौर में दूसरा गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) का बना तब इनके सदन में 28 सदस्य थे। केएमपीपी की स्थापना आचार्य जी बी कृपलानी ने कांग्रेस से असंतुष्ट होने के कारण की थी।

तीसरा गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टियों का था जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सात में से 6 सदस्य एवं आधे दर्जन से ज्यादा स्वतंत्र सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा एक चौथा गठबंधन जयपाल सिंह के नेतृत्व में बना जिसमें झारखंड पार्टी के तीन सदस्यों के अलावा चार राजा, तीन जागीरदार व एक बड़े व्यवसायी का नाम शामिल था। सदन के भीतर बने इस गठबंधन के किसी भी समूह के पास सदन के कुल सदस्यों का 10त हिस्सा नहीं था ताकि विपक्ष के नेता के लिए सदन की मान्यता हासिल हो सके।

सदन के बाहर 1971 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था। इसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। इसे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला पूर्ण गठबंधन कहा जाता है। सन 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल सहित पूरा विपक्ष मिलकर 1977 चुनाव में उतरा और दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस (इ) को उखाड़ फेंका। इसके बाद वर्ष 1989 में जनता दल के नेता वीपी सिंह ने तेलुगू देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था।

यह मोर्चा सरकार बनाने में तो सफल हुआ लेकिन जल्दी ही बिखर गया। आगे चलकर जनता दल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। वर्ष 1999 में हुए 13 वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 16 दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन किया। वाजपेई जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस गठबंधन में नेशनल कान्फ्रेंस, मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित कुछ अन्य छोटे दल भी जुड़े। वर्ष 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी यूपीए का गठन किया।

हालांकि नीति कार्यक्रम और सिद्धांत के आधार पर सबसे लंबा गठबंधन पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का रहा है लेकिन चूंकि अब वे %न तीन में रह गए हैं न तेरह में%, इसलिए उनकी गिनती तो छोड़िए चर्चा तक बेमानी हो गई है। हाल के वर्षों में केंद्र से लेकर राज्यों तक समय-समय पर बनने वाले गठबंधनों को देखकर लगता है कि गठबंधन बनते ही हैं बिगड़ने के लिए। विडंबना यह है कि गठबंधन बनाते समय जोर चेहरे पर रहता है, चाल और चरित्र पर नहीं। कई बार जनता को दिखाने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी बनाया जाता है पर वास्तव में साझा कार्यक्रम सत्ता की बंदरबांट का ही होता है।

याद करिए मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में घटक दलों के बीच मलाईदार मंत्रालयों को लेकर कितने दिन तक तमाशा चला था। हाल में महाराष्ट्र की घटनाओं ने गठबंधन राजनीति की विद्रूपताओं को सरेआम कर दिया है। आज बड़े दलों के साए में गठबंधन में शामिल छोटे दलों की हैसियत सजावटी बारातियों जैसी हो गई है। अंग्रेजी राज में जिस तरह बड़ी तादाद में राजा महाराजा अंग्रेज बहादुर को समर्थन देने के लिए उमड़ पड़ते थे, कमोबेश उसी तरह आज छोटे दल अपने निहित स्वार्थ के कारण घोषित नीति से समझौता करके जुड़ जाते हैं। यही वे दल हैं जो छोटी-छोटी बातों पर भी गठबंधन धर्म का मर्म भूल बिदक कर कहीं और चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कभी यहां कभी वहां के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है।

बहरहाल पिछले 25 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर दो दीर्घजीवी और सफल गठबंधन रहे हैं। पहला भाजपानीत एनडीए और दूसरा कांग्रेसनीत यूपीए। एनडीए का यह सिल्वर जुबली वर्ष है। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष अब नया गठबंधन बनाने में जुटा है, लेकिन लगे हाथों एनडीए के शिविर में छोटे बड़े हर तरह के दलों को शामिल करने की भाजपाई कवायद से यह साफ संकेत मिलता है कि गठबंधन की राजनीति का दौर आगे भी बदस्तूर चलने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि गठबंधन राजनीति की तेजी से गिरती साख को बचाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ-साथ नीति और सिद्धांत के आधार पर भी एकजुटता की जमीन तैयार की जाए ताकि मौकापरस्तों की मनमानी से बचते हुए स्थिर सरकार और सुशासन का आधार मजबूत हो।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-9)

गतांक से आगे...

अपान वायु को इन्द्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए तथा दोनों हाथों को अँगुलियों) से दोनों कानों को बन्द कर लेना चाहिए। इस क्रिया (षण्मुखी मुद्रा- दोनों हाथों की अँगुलियों से आँख, कान, मुख, नाक आदि बन्द करने से मन को वशीभूत कर लिया जाता है। इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्राणवायु नियमित हो जाता है एवं नासिका द्वारा क्रमानुसार उसका आवागमन प्रारम्भ हो जाता है।

मुख्य तीन नाड़ियाँ हैं। उनमें प्राणायाम करने वाले साधकों का श्वास दायें एवं बायें नासापुटों के द्वारा समान समय तक क्रियाशील होकर चलता रहता है। इस तरह से जिसका प्राण क्रमपूर्वक सक्रिय रहता है, वह प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् वह योगी दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अन्तर्मुखी होकर जानने में समर्थ हो जाता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है।

अंगुष्ठादि अपने अंगों का स्फुरण (अर्थात् नाड़ी संस्थानों में रक्त गति से फड़कना) बन्द हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन का समापन समझ लेना चाहिए। ऐसे अनिष्ट सूचक संकेतों को जानने के पश्चात् श्रेष्ठ योगी-साधक को अपना पूरा ध्यान मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। जिसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथ के अंगूठों में स्फुरण न होते जान पड़े, तो यह जानना चाहिए कि उसका जीवन मात्र एक वर्ष में समाप्त होने वाला है। मणिबन्ध (कलाई) एवं गुल्फ (टखना) का स्फुरण जब बन्द हो जाये, तो मनुष्य मात्र छः मास तक ही जीवित रहता है और जब हाथ की कोहनी में स्फुरण न हो, तो जीवन की अवधि मात्र तीन मास ही शेष बचती है। कुक्षि (पेट के अगल-बगल का हिस्सा) और उपस्थेन्द्रिय (लिंग) में स्फुरण न हो, तो मात्र एक मास में जीवन समाप्त हो जाता है और चक्षुओं में स्फुरण न हो, तो मात्र पन्द्रह दिन में ही जीवन समाप्त हो जाता है।

जठर द्वार पर जब स्फुरण न हो, तब जीवन की अवधि मात्र दस दिन शेष बचती है और (सूर्य-चन्द्र की) ज्योति जब जुगनू के समान हो जाये, तो फिर पाँच दिन ही शेष रह जाते हैं। जिह्वा के अग्रभाग का दर्शन जब बन्द हो जाये, तो फिर तीन दिन का ही समय शेष समझना चाहिए और जब ज्वाला का दिखाई पड़ना बन्द हो जाये, तो दो ही दिन शेष जानना चाहिए।

क्रमशः ..

डॉ. खूबचंद बघेल : छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा

प्रदेश आज डॉ. खूबचंद बघेल की जयंती मना रहा है। डॉ. बघेल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की नींव रखी। वे जाति, धर्म, भाषा, मूल निवासी की संकुचित अवधारणाओं से परे थे। उनका मानना था कि 'छत्तीसगढ़िया' वही है जो छत्तीसगढ़ के हित की बात करता है। अपने जाति के संगठन के मुखिया होने के बाद भी उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के संचालन के लिए भ्रातत्व संगठन का गठन किया, जिसका एक व्यापक जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष आधार था।

डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म रायपुर जिले के पथरी गांव में 19 जुलाई, 1900 को हुआ था। उनके पिता का नाम जुड़ावन प्रसाद एवं माता का नाम केतकी बाई था। डॉ. खूबचंद बघेल ने वर्ष 1920 में नागपुर के राबर्ट्सन मेडिकल कालेज से शिक्षा ग्रहण किया। नागपुर में ही उन्होंने विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मेडिकल कोर के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। डॉ. बघेल महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ गांधीजी से जुड़ने का फैसला किया और साल 1930 में गांधीजी के आंदोलन से जुड़ गए। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। आजादी के बाद उन्होंने 1951 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आचार्य कृपलानी के साथ 'किसान मजदुर प्रजा पार्टी' से जुड़ गए। डॉ. बघेल को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा भी कहा जाता है।

डॉ. बघेल खुले विचारों के थे। उन्होंने कुप्रथा का जमकर विरोध किया। होली के दौरान कराये जाने वाले 'किसबिन नाच' को बंद कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और इसमें सफल भी रहे। इसके अलावा उन्होंने 'पंक्ति तोड़ो' आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य था 'कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर सकता है'। जाति के आधार पर अलग पंक्ति नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन में भी डॉ. बघेल सफल रहे। खूबचंद बघेल का हमेशा से सामाजिक कुरीतियों को देखकर खून खौल उठता था। हमेशा इन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किये। जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेकों बार समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में छुआछूत, ऊँच- नीच की भावना व्याप्त थी। खूबचंद बघेल ने जब से अपना होश सम्हाला था, तब से उन्हें जातिगत भेद भाव से चिढ़ थी। उन्होंने जातिगत भेद भाव के साथ साथ उपजातिगत भेद भाव को भी दूर करने का काम किया जिसके फलस्वरूप आज के समय में कुर्मी समाज में व्याप्त उपजाति भेदभाव को दूर किया जा सका है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए डॉ. बघेल जी स्वयं मनवा कुर्मी के थे, परन्तु उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह दिल्लीवार कुर्मी समाज में तथा सबसे छोटी बेटी का विवाह पटना के राजेश्वर पटेल जी से करवाया; फलस्वरूप उन्हें समाज के क्रोध के कारण कुर्मी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। परन्तु वे हमेशा से इस उपजाति बंधन को तोड़ने में लगे रहे। खूबचंद बघेल हमेशा से छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए कार्य किया, वे हमेशा छत्तीसगढ़ के दब्बूपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये,वे हमेशा यही चाहते थे की छत्तीसगढ़ को लोग क्यों ऐसे हीन भावना से देखते है हमेशा इससे सौतेला व्यावहार क्यों करते हैं बस इन्ही बातों की चिंता उन्हें सताते रहती थी। इस महान व्यक्ति का निधन संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाग लेने दिल्ली गए हुए थे वहाँ दिल का दौरा पड़ने से उनकी आकस्मिक निधन 22 फरवरी 1969 को हो गया।

यूएई और भारत की गाढ़ी होती दोस्ती

प्रोफेसर एके पाशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात (यूएइ) की राजधानी अबू धाबी का दौरा करना दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण दोनों देशों का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष दोनों पक्षों का आपसी व्यापार 85 अरब डॉलर के करीब रहा। इसमें तेल का व्यापार भी शामिल है। मगर, गैर-तेल उत्पादों का भी निर्यात लगातार बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में यह आपसी व्यापार घोषित लक्ष्य को पार कर जाएगा। भारत-यूएइ का कारोबार पिछले साल मई में दोनों देशों की समग्र आर्थिक सहयोग संधि के लागू होने के बाद 15 प्रतिशत बढ़ा है। किसी भी और देश के साथ भारत का कारोबार इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएइ के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान की मुलाकात में एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने को लेकर हुई है। आज डॉलर जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, उससे अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में भारतीय उत्पाद कम होते जा रहे हैं। दरअसल, यूएइ भारतीय निर्यातकों के लिए एक हब जैसा है। यदि रुपये या दिरहम में व्यापार शुरू हो जाएगा तो भारत का निर्यात बहुत जल्दी दोगुना बढ़ सकता है। यूएइ तब भारत से ज्यादा सामान खरीद कर उन्हें पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप या पूरे अरब जगत में बेच सकता है। महंगे डॉलर की वजह से भारत इतना निर्यात नहीं कर पा रहा है।

तीसरा महत्वपूर्ण कदम यूएइ में काम कर रहे या वहां घूमने जाने वाले भारतीयों के बारे में उठाया गया है। वे अब भारत के बैंकों या दूसरे वित्तीय संस्थानों के क्रेडिट कार्ड का यूएइ में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे वहां रहने वाले भारतीय आसानी से पैसे भेज सकेंगे। इस फैसले से ऐसे लेन-देन को आयकर के दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल, ऐसे लेन-देन हवाला के जरिये होते हैं, जिससे भारतीय

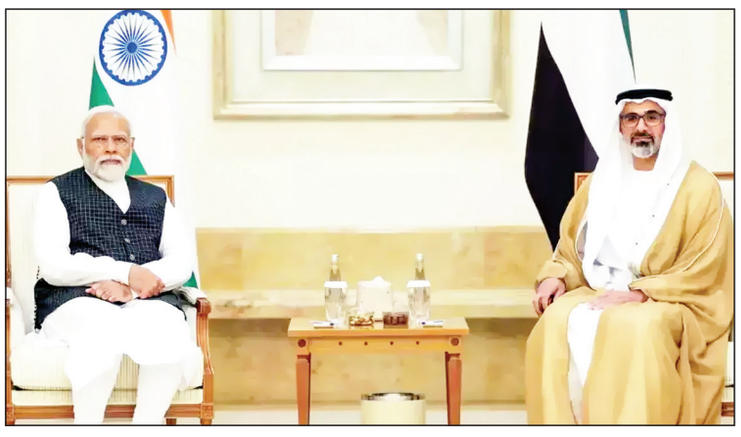

बैंकों या भारत के सरकारी खजाने को जितनी कमाई होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। यह हवाला जैसे गैर-कानूनी कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है। इससे वहां रह रहे भारतीयों या किसी अन्य देश के लोगों द्वारा दुबई के रास्ते तस्करी या अन्य जरियों से सोना या दूसरी चीजें लाने के चलन में भी कमी आयेगी। अब चूंकि दोनों ही देश अपनी-अपनी मुद्राओं या क्रेडिट कार्ड से लेन-देन कर सकेंगे, तो इससे दोनों ही सरकारों को फायदा होगा।

इससे अब तक नाजायज फायदा उठाते रहे तीसरे पक्षों का असर कम हो जाएगा। दुबई से शुरू हुआ काले धन के आपराधिक कारोबार का ये सिलसिला पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और कैरीबियाई देशों तक पहुंच गया था, जिससे भारत को नुकसान हो रहा था। स्थानीय मुद्राओं में कारोबार होने से यूएइ भारत में भी सीधे निवेश कर सकता है। भारत और यूएइ की ओर से लिया गया यह एक ठोस कदम है। अरब के दूसरे देश जैसे सऊदी अरब और कतर ने बहुत लंबे-चौड़े वादे किए, मगर केवल खाड़ी के देश यूएइ ने एक उपयुक्त ढांचा बना कर और वास्तविक निवेश की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाया है।

भारतीय प्रधानमंत्री ने अबू धाबी पहुंच कर यूएइ के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायेद से कहा कि 'हर भारतीय उन्हें एक सच्चा दोस्त मानता है'। दरअसल, भारत और यूएइ की दोस्ती बहुत पुरानी है। दशकों पहले भारत के गुजरात और पश्चिमी राजस्थान से लोग दुबई गये थे। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार और अन्य शहरों में जब राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ, तो इन ईरानी शहरों और इराक के बसरा से सभी गुजराती और राजस्थानी व्यापारी दुबई चले आये। यह पहले विश्वयुद्ध के बाद हुआ। तभी से दुबई भारत और खाड़े के अन्य देशों के बीच व्यापार का एक केंद्र बन गया। वहां से तब मोती, खजूर और घोड़े आया करते थे। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब अरब जगत में तेल का भंडार मिला, और तेल से कमाई होने लगी, तो वहां भारतीय उपभोक्ता सामग्रियों की मांग बढ़ने लगी। इनमें चावल, मसाले, कपड़े और फर्नीचर जैसी चीजें शामिल थीं।

वर्ष 1973 के बाद जब यूएइ में पेट्रो डॉलर आने शुरू हुए तो भारत के लोगों ने वहां बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां हासिल करनी शुरू कीं। हालांकि, तब राजनीतिक तौर पर दोनों देशों का संपर्क कमजोर रहा। वर्ष 1981 में इंदिरा गांधी की यूएइ यात्रा के बाद लंबे समय तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएइ का दौरा नहीं किया। वर्ष 2015 में, प्रधानमंत्री मोदी 34 साल बाद यूएइ जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके अगले साल, 2016 में शेख मोहम्मद बिन जायद भारत आये और इसके अगले साल, यानी वर्ष 2017 में, वह भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आये। मगर 1981 के बाद से राजनीतिक तौर पर संपर्क भले ही न हुआ हो, मगर दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों का संपर्क बढ़ता गया। साथ ही, दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते गये। इन वजहों से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का एक आधार तैयार हो गया था। इसे वर्ष 2014 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएइ का दौरा कर दृढ़ता प्रदान की। भारत ने यूएइ के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी की और उसे रणनीतिक तौर पर बहुत महत्व दिया। आज यूएइ भारतीय विदेश नीति का एक आधार-स्तंभ बन चुका है। भारत ने यूएइ के साथ-साथ पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में सऊदी अरब और इसराइल के साथ भी एक सकारात्मक और संतुलित रणनीति को अपनाया है।

भारत और यूएइ की दोस्ती दोनों ही पक्षों के साझा हित पर टिकी है। दुबई के शेख व्यापार के मामले में गुजरात के कारोबारियों से भी आगे समझे जाते हैं। बिना किसी फायदे के वे किसी की ओर निगाह उठा कर भी नहीं देखते। कारोबार की ऐसी समझ और तजुर्बे की ही बदौलत उन्होंने खाड़ी में सबसे शानदार शहर बसा लिया है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान या ईरान जैसे देश भी दुबई के जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन, कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अबू धाबी और दुबई के शेख काफी दूर की सोचते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले समय में अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया है और अब उनका ध्यान भारत पर ज्यादा है।

बापू की दिनचर्या

डायरी-लेखन और माला-जप

शयन से पूर्व बापू आश्रम की व्यवस्था तथा उसके हिसाब-किताब की जाँच करते, कुछ लिखते-पढ़ते और सार्थक चर्चा करते। पैसे-पैसे का हिसाब माँगते। सच्चे अर्थों में वे सार्वजनिक धन के सजग प्रहरी थे। लिखने-पढ़ने में डायरी-लेखन का मुख्य स्थान होता। बापू दिनचर्या का क्रम बनाकर और नियमपूर्वक डायरी लिखकर अपने जीवन के सभी कार्य संतुलित रखा करते। आश्रमवासियों के लिए उनका यही आदेश सदा रहता। सत्य एवं नैतिकता के हर साधक के लिए डायरी-लेखन वे आवश्यक मानते। डायरी-लेखन बापू की आत्मपरीक्षण या आत्मशुद्धि की निरंतर प्रक्रिया थी। अपने लिए उसे वे बहुमूल्य वस्तु मानते। कहते कि सत्य के आराधक के लिए वह रखवाले का काम करती है, क्योंकि उसमें सत्य का उल्लेख होता है। आलस्य या पूरा काम न करने पर भी उसमें स्पष्ट उल्लेख किए बिना चल नहीं सकता। इस तरह वह हर प्रकार से हमारे रक्षक या पहरेदार की भूमिका अदा करती है। वे इसका महत्त्व महसूस करने पर हमेशा बहुत बल दिया करते। कहते कि एक बार नियमपूर्वक लिखना आरंभ करने पर खुद सारी बातें अपने-आप सूझने लगती हैं; किंतु मुख्य बात सत्य की है, जिसके कारण वह स्वर्ण की मुहर से भी मूल्यवान् हो जाती है। असत्याचरण या सत्य के अभाव में उसे वे मुहर के बजाय खोटे सिक्के की संज्ञा देते। बापू डायरी-नागे, नियमित लिखने को कहते। उनके अनुसार इसका लाभ तत्काल नहीं, बाद में ज्ञात होता है। बताते थे कि इस नियम का पालन करने से हम अनेक दोषों से बच सकते हैं, क्योंकि वह हमारे अपराधों अथवा हमारी त्रुटियों की साक्षी होती है। अपने दोषों का उसमें अवश्य जिक्र होना चाहिए, किंतु दूसरों के दोषों का जिक्र तथा उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। आत्मप्रशंसा को भी उसमें स्थान नहीं मिल सकता। किए गए कार्यों और बन बड़े अपराधों का उल्लेख मात्र होना आवश्यक है। बापू का यह भी कथन था कि रोज-रोज डायरी लिखने से ऊबना और उसमें इत्यादि जैसे शब्द का उल्लेख सर्वथा अनुचित है हमारा सारा कार्यक्रम पूरी तरह व्यवस्थित रहे-समय पर हमारे सभी काम संपन्न हों, तो डायरी लिखने में कठिनाई उपस्थित होने का कोई प्रश्न नहीं। इस प्रसंग में वे सूर्य के नित्य उदय होने की मिसाल देते हुए उससे सबक लेने को कहते। उनका कथन था कि मनुष्य को यंत्र बनकर नहीं, बल्कि यंत्र की भाँति अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों मिला भूमि सम्मान

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। उसके साथ ही प्रदेश के दो जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए है, जिससे आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां मिलना आसान हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तर में नीलम नामदेव एक्का सचिव राजस्व विभाग, किरण कौशल महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रमेश शर्मा संचालक भू-अभिलेख ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के हाथों लैंड गवर्नेंस और प्रशासन में छत्तीसगढ़ को मिला भूमि सम्मान ग्रहण किया। इसी प्रकार बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा और सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान ग्रहण किया।

फूलोदेवी नेताम ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

रायपुर। सांसद फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। फूलो देवी नेताम ने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। फूलो देवी नेताम पिछले सात साल से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर थीं। वर्तमान में फूलो देवी नेता राज्यसभा सांसद भी हैं। इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि लंबे समय तक इस पद पर रहने के बाद किसी और को यह जिम्मेदारी देने के लिहाज से उन्होने यह इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।

संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात

रायपुर। छग सेजेस संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री से सौजन्य भेंट कर धन्यवाद ज्ञापन देने और विभिन्न मांगों को रखने की सहमति बनी। इनसे सौजन्य भेंट का समय लेने का प्रयास किया गया। किन्तु मुख्यमंत्री की व्यस्तता और पूर्व अनुमति न होने कारण भेंट प्रक्रियाधीन रहा। जबकि उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, शिक्षामंत्री रविन्द्र चौबे से सौजन्य मुलाकात कर संघ के सभी साथियों द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को उनके समक्ष रखते हुए ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कुमार साहू, प्रदेश महासचिव उनीत साहू, संस्थापक सदस्य शक्ति खरे राजू पटेल संभाग अध्यक्ष दुर्ग हरिकृष्ण भोगल, रायपुर संभाग अध्यक्ष ललित बर्मन बिलासपुर से नित्यानंद मालाकार, सरगुजा से उमेश शर्मा और बस्तर से कल्पना घृतलहरे तथा अन्य साथीगण जिसमे जिला अध्यक्ष, चंद्रकांत यादव, हामिद खान, तनु, पीटर तिग्गा, रौनक अग्रवाल कंचन धनगर, प्रीति पंतवाने , आकाश विश्वास , यादवेंद्र वर्मा आदि शामिल हुए।

शराब घोटाले मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को राहत देते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच पर रोक लगा दी है। ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। बतादें कि ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ। वहीं कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर दावा किया है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दो हजार करोड़ की मनी लांड्रिग के सबूत मिले हैं। उन्होंने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि कारोबारी छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहे हैं और उसमें बड़े नेताओं के अलावा सीनियर अफसरों का भी सपोर्ट है,जिसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी, इसमें ईडी ने कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की है।

मुख्यमंत्री ने डॉ. खूबचंद बघेल की जयंती पर उनके योगदान को याद किया

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉ. खूबचंद बघेल की 19 जुलाई को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बघेल का छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि खूबचंद जी किसान-मजदूर हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के हितचिंतन में लगा दिया। खूबचंद जी ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की।

किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान

सहकारी समितियों को मजबूत करने पर दिया बल, धान खरीदी व्यवस्था के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न

■ **धान खरीदी के लिए बारदाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देश**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यों में कृषि उत्पादन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर बैठक में शामिल हुए। बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता मंत्री श्री रवीन्द्र चौबे भी जुड़े। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी का संचालन किया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी किया जाना है। इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है। धान खरीदी के साथ-साथ धान के उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से संपन्न हुआ है। इस वर्ष भी किसानों को सहुलियत प्रदान करने और धान विक्रय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज भाई तंबोली, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रितेश अग्रवाल, खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री एम. सोनी, फुड एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक श्रीमती रानू साहू, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के. एन. कान्डे सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर दक्षिण का किला ढहाने कांग्रेस को सेनापति की तलाश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरु हो गई है। पार्टीगत रणनीति बनने लगे हैं,वहीं दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। वैसे तो राज्य में 90 सीटों पर चुनाव होना है,पर कुछ हाट सीट हैं जिन पर नजरें लगी हुई हैं उनमें से एक है रायपुर दक्षिण विधानसभा यहां से कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है.पार्टी ऐसी सीटों पर मजबूत दावेदार की तलाश में है। हालांकि यहां से हर बार नए चेहरे ही उतारे गए,पराजित प्रत्याशी को दोबारा मौका नही मिला। आंतरिक तौर पर सर्वे व हार जीत के कारणों को तलाशा गया है जिसमें यह बात सामने आई है कि उसी की तर्ज पर ऐसा सर्वमान्य चेहरा उतारा जाए जो जनता के बीच सामान्य रूप से मेलजोल रखता हो। क्योंकि पार्टी का परम्परागत वोट तो टूटने से रहा। राज्य सरकार का बेहतर कामकाज व सीटिंग विधायक की नाराजगी इसमें प्लस का काम करेगा। इन सबके बीच मुद्दे की बात जो सामने आ रही है ऐसी सीटों पर कम से कम दो से ढाई माह पहले प्रत्याशी घोषित किया जाए ताकि तैयारी के लिए मौका मिल सके,और यहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ जाती है।

दक्षिण का किला ढहाने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत सेनापति की तलाश है। चुनावी चर्चा के बीच एक प्रमुख नाम रायपुर नगर निगम के वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे का उभर कर सामने आया है। अब नाम उछलते ही सवाल भी उठने लगे कि आखिर प्रमोद दुबे क्यों..? इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण गिनाये जा रहे हैं कि वे महापौर भी रह चुके हैं और अब सभापति इसके साथ दक्षिण विधानसभा के तीन अलग अलग वार्डो से वे पार्षद भी निर्वाचित होते आ रहे हैं। पहली बार ब्राम्हणपारा,दूसरी बार रामकुंड व तीसरी बार पंडित भगवतीचरण शुक्ल वार्ड से चुनाव जीते हैं। निगम की राजनीति में सक्रिय रहने से शहरी जनता से सतत संपर्क बना हुआ है। छात्र राजनीति में रविवि के अध्यक्ष रहे हैं। विभिन्न सामाजिक,सांस्कृतिक व खेल संगठनों से जुड़े होने का फायदा भी मिलेगा। सुख और दुख के मौकों पर शहर में कहीं पर भी प्रमोद दुबे की मौजूदगी दिख जायेगी। वैसे कांग्रेस ने कभी जातिगत राजनीति या समीकरण को तवज्जो नहीं दिया है,मापदंड केवल मजबूत जनाधार वाला जीत योग्य चेहरा रहा है। दक्षिण विधानसभा में 42 हजार ब्राम्हण,18 हजार मुस्लिम व 17 हजार उत्कल मतदाता हैं। यही निर्णायक मतदाता हैं।

जनता से सीधे जुड़े दो बड़े अभियान जिसे शहर के लोगों ने भरपूर सराहा और सहभागिता निभाई। एक नशे के खिलाफ जनजागरूकता को लेकर -नशे के विरुद्ध जंग- नाम देकर विभिन्न संगठनों व महिला समूहों को जोड़कर विविध आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने नो व्हीकल डे के नाम से साइकिल चलाने का संकल्प दिलाया। इस अभियान में शहर का हर वर्ग जुड़ा। प्रमोद दुबे की एक पहचान ठेठ छत्तीसगढिय़ापन भी है। आजकल पूरे सूबे में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढिय़ा से जुड़े तीज त्यौहार,खान पान, बोली भाखा में छत्तीसगढिय़ा को पसंद किया जा रहा है।

कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं: रिजवी

■ **जब तक दल का बी फार्म न मिल जाए तब तक टिकिटार्थी को सतर्क एवं चौकन्ना रहना चाहिए**

रायपुर। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने बताया है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में कसडोल विधानसभा के पूर्व विधायक एवं मंत्री स्व. कन्हैयालाल शर्मा के पास जब भी कोई कांग्रेस की टिकट के लिए सिफारिश करवाने जाता था तब स्व. मंत्री जी कहा करते थे कि कांग्रेस की टिकट एवं मौत का कोई भरोसा नहीं कब किसके पास पहुंच जाए। स्व. शर्मा जी का उक्त जुमला उस समय बहुत सुर्खियों में रहा था तथा मीडिया में भी उनकी इस टिप्पणी का जिक्र हुआ था तथा स्व. शर्मा जी ने न अपने जुमले को बाद में वापस ले लिया था वरन् वह कहा करते थे कि उनकी उपरोक्त टिप्पणी कांग्रेस में अपने अनुभव के आधार पर ही है।

रिजवी ने स्व. शर्मा की टिप्पणी पर काफी हद तक सहमति व्यक्त करते हुए अपने 45 साल के अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि उक्त टिप्पणी पर हतोत्साहित न हों वरन् टिकट प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास करते रहना चाहिए तथा जब तक दल का बी फार्म न मिल जाए तब तक टिकिटार्थी को सतर्क एवं चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि पूर्व में ऐसे कई उदाहरण है कि टिकट जिसको मिला था वह देखता रह जाता था और बी फार्म किसी और के द्वारा ऐनकेन प्रकारेण हासिल कर लिया जाता था। कांग्रेस हाईकमान द्वारा भी ऐसी अनुशासनहीनता के लिए कभी भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। सन् 1993 में खुज्जी, विरेन्द्र नगर एवं पाटन विधानसभा क्षेत्र के दलीय घोषित प्रत्याशी को बी फार्म किसी और को दे दिया गया था तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशी के स्वतंत्र चिन्ह दे दिए गए थे और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी चुनाव हार गए थे।

डॉ. खूबचंद बघेल ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को दी नई दिशा: बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉ. खूबचंद बघेल की 19 जुलाई को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बघेल का छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि खूबचंद जी किसान-मजदूर हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के हितचिंतन में लगा दिया। खूबचंद जी ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। साहित्य सृजन, लोकमंचीय प्रस्तुति तथा बोल-चाल में वे छत्तीसगढ़ी के पक्षधर थे। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा के रूप में भी जाने जाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अध्ययन के दौरान ही डॉ. साहब राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने लगे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने गांव-गांव घूमकर सैकड़ों युवाओं को स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित किया और स्वाधीनता संग्राम से उन्हें जोड़ा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके द्वारा लिखे नाटकों ने भी जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला।डॉ. बघेल की स्मृति और सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एक जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के 69 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं।

भाजपा 20 को करेगी विधायक निवास का घेराव

दंतेवाड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी ने बताया कि भाजपा कार्यलय में हुई बैठक में लिए गये निर्णयानुसार वर्ष 2021 धान खरीदी के 04 किस्त की राशि को अविलंब प्रदाय करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु निःशुल्क अनाज जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का प्रदाय करने, जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत एवं अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूर्ण करने, जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो की विद्युत् व्यवस्था सुधारने, जिला के मुख्य मार्ग की सड़क व्यवस्था सुधारने, जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण और उपकरणों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने, जिला खनिज न्याय निधि के मद द्वारा किये गये निर्माण कार्यो की जांच करने, विधायक देवती कर्मा व छबिंद्र कर्मा जिले के निर्माण कार्यो में रेत की खुलेआम तस्करी बंद करने एवं तेंदूपत्ता संग्रहको का खरीदी दर अनुसार नगद भुगतान करने, अमृत सरोवर योजना और जिले में विभिन्न तालाब के निर्माण कार्यो की जांच करने, इन सभी मांगो व स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा दंतेवाड़ा 20 जुलाई को विधायक देवती कर्मा के निवास का घेराव करेगी।

यूपीएससी परीक्षा को लेकर टॉपर्स टॉक

■ **21 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा आयोजन**

रायपुर। यदि हमारी शहर के युवा यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएसी-आईपीएस अफ्सर बनना चाहते है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे शहर में टॉपर्स टॉक का आयोजन हो रहा है। यह 21 जुलाई सुबह 10 बजे पं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। उस दिन बैच 2022 के यूपीएससी टॉपर युवाओं के बीच होंगे और अपने सफ्लता के अनुभव साझा करेंगे।

इस दिन छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के टॉपर्स से मिलने, बात करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। यूपीएससी परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर चयनित टॉपर्स रायपुर आ रहें है। यूपीएससी की 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकेण्ड टॉपर गरिमा लोहिया और नौवाँ स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल भी रायपुर आ रहीं हैं। साथ ही 2022 की परीक्षा में 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर भी इन टॉपर्स के साथ रहेंगे।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस बारे में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर चयनित होने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 21 जुलाई को टॉपर्स टॉक आयोजित की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से होने वाली इस टॉपर्स टॉक में स्थानीय प्रतियोगियों को चयनित टॉपर्स से यूपीएससी क्रेक करने की टिप्स मिलेंगी। यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षा को क्रेक करने के लिए पढ़ने के तरीके, पढ़ने का सिलेबस, समय प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या से लेकर मनोरंजन, खाने पीने से लेकर अन्य सभी विषयों पर टॉपर्स के सुझाव स्थानीय प्रतिभागियों को मिलेंगे।

डॉ. भुरे ने बताया कि टॉपर्स टॉक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना है।

सुप्रीम कोर्ट की रोक से साफ है ईडी की कार्यवाही विद्वेषपूर्ण: कांग्रेस

रायपुर। उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले की जांच पर रोक यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि ईडी की कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक और राजनैतिक साजिश है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर राजनैतिक रूप से सीधा मुकाबला नहीं कर पाती, वहां पर वह केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर अपना राजनैतिक मंतव्य साधने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला ईडी के द्वारा रची गयी पटकथा है जो राज्य सरकार की छवि खराब करने के लिये है। राज्य में भाजपा के पास जनसरोकारों का कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा लगातार राज्य में जनता का भरोसा खोते जा रही है उसके कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है ऐसे में अपने राजनैतिक वजूद को बचाने भाजपा ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की छवि खराब करने में लगी है। पिछले चार साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर भाजपा 1 रू. का भी प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाई है तो अधिकारियों, व्यापारियों के यहां छापेमारी कर सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने की तैयारी की जा रही थी।

शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मोदी सरकार की राजनैतिक विरोधियों के दमन का हथियार बन चुकी है। विपक्ष की आवाज दबाना तथा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने मोदी सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। मीडिया जब छापती है तो केंद्रीय एजेंसियों से छापा मरवाते है, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देते, न्यायपालिका को सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करते है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आपने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के खिलाफ फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन बना रखा है।

पिछले 9 सालों में सीबीआई, आईटी और ईडी की छापेमारी का सबसे प्रमुख कारण राजनैतिक बदला भांजना रहा है। पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां अपराध रोकने, कर अपवचन रोकने कार्यवाही करती थी मोदी राज में जांच एजेंसियां विरोधियों को फंसाने उनको बदनाम करने षड़यंत्र करती है झूठा केस बनाती है। ईडी ने पिछले 8 सालो में 3010 छापे मारे है। जिनमें से 95 प्रतिशत गौर करें-कांग्रेस (24), टीएमसी (19), एनसीपी (11), शिवसेना (8), डीएमके (6), बीजद (6), राजद (6), बीएसपी (5), एसपी (5), टीडीपी (5), इनेलो (3), वाईएसआरसीपी (3), सीपीएम (2), एनसी (2), पीडीपी (2), इंडस्ट्रीज (2),एआईएडीएमके (1), एमएनएस (1), बीएसपी (1)। यह छापे इस बात का प्रमाण है कि भाजपा जब राजनैतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है।

शुक्ला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश भर में अपने मुखर विरोधी राज्य सरकारों के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है। विरोधी दलों की सरकारों को प्रताड़ित करने का काम किया है। पं. बंगाल में तृणमूल की ममता बेनर्जी, झारखंड हेमंत सोरेन सरकार, दिल्ली के केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, पंजाब की पूर्व कांग्रेस की चन्नी सरकार जैसे अनेकों उदाहरण जहां पर भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से भय और आतंक फैलाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में की गयी ईडी की कार्यवाही भी भाजपा के उन्हीं षड़यंत्रों का हिस्सा है।

युवाओं का निर्वस्त्र प्रदर्शनः भाजपा ने किया राजभवन मार्च

रायपुर। रायपुर में विधानसभा रोड पर एससी-एसटी युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। आमासिवनी के पास फर्जी आरक्षण प्रमाणपत्रों का आरोप लगाते हुए करीब 12 युवाओं ने पूरी तरह नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वालों का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियों से मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में 29 प्रदर्शनकारी युवाओं को गिरफ्तार किया है। सभी पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। विधानसभा रोड थाना क्षेत्र का मामला है।

प्रदर्शन कर रहे एससी-एसटी युवाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित

वर्ग के कोटे का शासकिय नौकरियों एवं राजनैतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता देखते हुए राज्य सरकार नें उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी। इसकी रिर्पोट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन अभी तक यह आदेश खानापूर्ति ही साबित हुआ।

बीजेपी ने इस मामले को लेकर सरकार पर आक्रामक है। मंगलवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली शर्मसार करने वाली घटना है। बीजेपी इस मामले को लेकर आज विधानसभा रोड का घेराव करने जा रही है। वहीं, इस संबंध में विधायक अजय चंद्राकर समेत बीजेपी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं।

यह सरकार की असफलता हैः डॉ. रमन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने मंगलवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए नग्न प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक पहल करने और प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भाजपा विधायक दल ने कहा है कि विधानसभा मार्ग पर पूर्णतः नग्न प्रदर्शन की मंगलवार को घटी इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। भाजपा विधायक दल ने अपराह्न 5.30 बजे अंबेडकर चौक में एकत्र होकर राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन के लिए पैदल कूच किया।

भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को सौंपे

अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण युवाओं में उपजा आक्रोश नग्न प्रदर्शन की हद तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली इस घटना में, प्रदेश के युवाओं ने पूर्णतः नग्न होकर विधानसभा के रास्ते पर प्रदर्शन किया। यह दुर्भाग्यजनक घटना न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि भारत के इतिहास में ही अपनी तरह की अकेली घटना है। इस घटना से छत्तीसगढ़ के लोग शर्मसार हैं। भाजपा विधायक दल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता और उसकी विभाजनकारी स्वार्थी राजनीति के कारण यह दुःखद परिस्थिति उत्पन्न हुई है। समाचारों के अनुसार इन युवाओं ने अपने इस प्रदर्शन की सूचना पहले ही शासन-प्रशासन को दे दी थी, बावजूद इसके शासन ने जरा-सी संवेदना दिखाने की जरूरत नहीं समझी। ये युवा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे उनका अधिकार छीने जाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल हरिचंदन से निवेदन किया है कि इस संवेदनहीन सरकार को तत्काल बर्खास्त कर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय।

बाबू भैया की कलम से

किसके राम के बाद हरेली किसकी पर रार

तुम हमारे राम को छीनने का प्रयास करोगे तो हम तुम्हारे हरेली, कांचा, भंवरा, गेडी, के मुद्दे को छोड़ेंगे क्या ? कभी नहीं। यही संदेश इस बार मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल द्वारा हर वर्ष अपने सरकारी निवास पर मनाए जाने वाले हरेली त्योहार को भाजपा ने भी मनाकर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह तो बिल्कुल ही सही कहा है कि हरेली त्योहार कोई भूपेश बघेल के आने के बाद ही छतीसगढ़ में नहीं मनाया जाने लगा। यह तो हमारी पारम्परिक त्योहार मनाने की सामान्य प्रक्रिया है और सदियों से मनाया जा रहा है। यह नहीं बताया गया कि अगर ऐसा ही है तो इससे पहले भाजपा ने अपने संगठन के द्वारा इसका कोई सार्वजनिक आयोजन क्यों नही किया, जो अब किया जा रहा है। बात साफ है , जिस राम को भाजपा अनेकों साल पहले से अपने राजनैतिक दायरे में लाकर राजनीति की नई सोच से काम कर रही है। सफलता भी मिली है। लगातार मात से कांग्रेस को राम को अपने पाले में करने की समझ आई। कांग्रेस ने शनैः शनैः श्री राम की राजनीति को अपने तरफ मोड़ने के लिए कौशल्या माता का भव्य मंदिर निर्माण,रामवन गमन पथ व उसके क्षेत्र में आने वाले राम द्वारा पवित्र किये गए स्थलों को सजाने ,प्रभु श्री राम की भव्य मूर्तियों का निर्माण करने,शिवरीनारायण में शबरी माता का मंदिर व प्रतीक बनवाने जैसा महत्वपूर्ण विषय हाथ में लिए। युद्ध गति से काम भी लगभग पूरा कर लिया। रही सही कसर रायगढ़ में भव्य रामायण महोत्सव करके पूरी कर दी।अब इस रामसेवा से लगता है प्रभु श्रीराम भी प्रभावित ही हुए होंगे। कांग्रेस तो यही मान कर ही चल रही है, पआशीर्वाद ही दिया होगा ,तभी तो राम के अनुयायी की तरह कांग्रेस अपने प्रचार में सफल हो रही है कि राम हमारे भांजे हैं। मां कौशल्या हमारी छतीसगढ़ महतारी के बेटी हैं। हमारे हैं जय सियाराम।

इधर जय सियाराम और उधर जयश्रीराम यानि राम भी राजनैतिक रूप से छतीसगढ़ में दो स्वरूपों में विभाजित से हो गये। अब राम को आप इस तरीके से अपनी ओर खिंचेंगें,तो आपका एजेंडा भी छीनने का प्रयास तो होगा ही । इस हाथ ले इस हाथ दे वाली शैली भाजपा ने भी अपना ली। हरेली में एक तरफ मुख्यमंत्री निवास पर हरेली की धूम थी तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी हरेली पर धूम मचा दी। अरुण साव,बृजमोहन अग्रवाल,संजय श्रीवास्तव के साथ अनेक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गेड़ी व भंवरा का भरपूर आनंद लेकर हरेली के इस आनंद को आत्मसात किया। भाजपा ने सिर्फ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही नहीं बल्कि तेलीबांधा तालाब के पास,पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मथुरा नगर में भी कार्यक्रम आयोजित किये। मथुरा नगर के डुमर तालाब में तो अरुण साव ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। बृजमोहन अग्रवाल,जयंती पटेल, और भी बड़े नेता शामिल हुए। चर्चा में है कि आखिरकार कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को संस्कृति का प्रदर्शन करने पर अपने तरीकों से मजबूर कर ही दिया। जिस तरह कांग्रेस ने राम को अपने पाले में किया है। भाजपा ने भी कमर कस कर उसका जवाब उसी की शैली में देने की कोशिश में की है। हालांकि भाजपा ने यह त्योहार राजनीति की छांव में पहली बार ही मनाया हो लेकिन कांग्रेस को कहना पड़ा कि भाजपा, कांग्रेस के भूपेश बघेल के असली पन की नकल कर रही है। नकल नकल ही होती है। अब राजनीति में राम असल में किसके हैं ,और छत्तीसगढ़िया संस्कृति के रक्षक कौन है ? यह जनता के विवेक पर ही छोड़ना होगा। चुनाव सर पर हैं ,दोनों दल अपने अपने आड़े तिरछे जो भी हो, दांव खेल रहे हैं। जनता में चर्चा इस बात की चल रही है कि कुछ भी हो पर भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़िया चेहरा जिस तरह उनकी ग्रामीण योजनाओं ने व संस्कृति की रक्षक के रूप में कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने बनाया है उसका कोई तगड़ा तोड़ अभी हाल तो भाजपा के पास दिखाई नहीं देता। बाजी पलटना है तो ईडी-आयकर बाद के लिए छोड़ कर , उन जमीनी स्थानीय बातों पर जोर देना पड़ेगा जिसका महत्व जनोन्मुखी हो। जनता के पेट की बात करनी होगी हंगामा खड़ा करने से बात नहीं बनेगी। समाधान पर बात होना चाहिए।

गठबंधन पर सियासी तंज

ये आईटी और ईडी से बचने के लिए एक समूह हैः सोनी

रायपुर। विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने पर सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा है. सांसद सोनी कहा, इनकम टैक्स और ईडी से बचने के लिए एक समूह है. यह समूह जिन्होंने राज्य और देश के पैसों को लूटा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है,मोदी को कोई नहीं डरा सकता. पीएम ने तय किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. जो लोग देश का पैसा लूट रहे है, सब के ऊपर कार्रवाई होगी. ईडी और आईटी जीतेगा.आगे सुनील सोनी ने कहा, सुना भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे. जो ईमानदार आदमी है वह चैन की नींद सुकून के साथ सोएगा.जनता जान रही है, कि समूह क्यों बना है. जनता को अब भ्रम में नहीं डाल सकते. 2024 नए भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है, स्वदेशी भारत का है.राहुल गांधी मामले को लेकर सुनील सोनी ने कहा, आप अहंकार और घमंड को त्याग देते तो अभी यह स्थिति नहीं आती.आपने तो अहंकार और घमंड के आधार पर स्वयं फैसला लिया, अब दर-दर भटक रहे हैं.

बच्चियों की मौतः रेत माफिया के संरक्षक भूपेश जिम्मेदार

रायपुर। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में अरपा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रेत माफिया इतना बेखौफ हो गया है कि आज भी आप किसी नदी की ओर जाएं, मशीनों से रेत खुदाई होते दिख जाएगी। बिलासपुर की अरपा नदी में दो सगी बहनें और एक चचेरी बहन की डूबने से मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके

जिम्मेदार अगर हैं तो रेत माफिया के सम्माननीय संरक्षक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। यह भाजपा का खुला कथन है। जनता की खुली आवाज है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि जो माफिया उस इलाके को पट्टे में लिया होगा, कितने का पट्टा मिला है कितनी खुदाई करनी है, एनजीटी के क्या निर्देश है, कौन इसकी जांच करेगा, अभी तक प्रशासन मौन है। उस परिवार से मिलने एक आदमी नहीं पहुंचा, जिनके बच्चों की मृत्यु हुई। उनके लिए एक रुपये की मुआवजा राशि की घोषणा नहीं हुई जो माफियाओं के कारण मरे। इस प्रकार पूरी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। यह सरकार माफिया के साथ खड़ी है। माफिया के पैसों के साथ खड़ी है। उसके अतिरिक्त शिवनाथ की धार बदल रही है। रेत कहीं दिखेगी नहीं। अरपा का भी हाल है। प्रदेश की जीवनदायिनी महानदी का भी वही हाल होने वाला है।भू जल संरक्षण का काम, पर्यावरण का काम छोड़कर सिर्फ अवैध तरीके से पैसा वसूलने का काम हो रहा है। मानव जीवन पर पैसा अर्जित करने का काम हो रहा है। यह नियत हो गई है सरकार की। अवैध कमाई का खून लग गया है। हमने जांच दल बनाया है। विधायक रंजना साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूजा विधानी, पुनीता डहरिया, जयश्री चौकसे इसमें शामिल हैं। इनको 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करने कहा है।

व्यर्थ नहीं जाएगा धर्म संस्कृति रक्षक का बलिदानः साव

- **भुनेश्वर साहू के परिवार को भाजपा ने दी 11 लाख की विनम्र सहायता**

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने बेमेतरा जिले के बिरनपुर में जेहादी उन्माद के शिकार हुए युवा भुनेश्वर साहू के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का चैक प्रदत्त किया। इस अवसर पर भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल भी उनके साथ रहे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व सांसद विजय बघेल ने स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के परिजनों से भेंट कर उन्हें सहायता राशि का चैक सौंपते हुए कहा कि भाजपा सदैव आपके साथ है। इस परिवार ने अपना सपूत खोया है। छत्तीसगढ़ महतारी ने भी अपनी एक युवा संतान को खोया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धर्म की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भुनेश्वर हम सभी के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। उनके निधन से परिवार, समाज

और छत्तीसगढ़ की जो क्षति हुई है, वह पूरी नहीं की जा सकती। भाजपा एक छोटा सा विनम्र सहयोग भुनेश्वर के उस स्वाभिमानी परिवार को समर्पित कर रही है, जिसने तुष्टिकरण की राजनीति में राजधर्म की बलि चढ़ाने वाली भूपेश बघेल सरकार की राशि और नौकरी ठुकरा दी। बिरनपुर में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में जिन्होंने उन्माद फैलाया, हिंसा में भुनेश्वर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उन सभी के खिलाफ नामजद शिकायत भुनेश्वर के पिता ने की थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने न तो उन सभी को गिरफ्तार किया और न ही जेहादियों को प्रोत्साहन देना बंद किया। बल्कि हेट स्पीच के नाम पर दमन शुरू कर दिया। पूरे छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस सरकार का असली चेहरा देखा है। इस अन्याय के खिलाफ भुनेश्वर के स्वाभिमानी परिवार का मुंह बंद करने कांग्रेस सरकार ने चंद रुपयों और एक नौकरी का प्रलोभन दिया। इस परिवार ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए भूपेश बघेल के मुंह पर उनकी खैरात फेंक दी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

विपक्ष का गठबंधन, देश के जनता की आवाजः दीपक बैज

रायपुर। साझा विपक्ष के 26 राजनैतिक दलों की बैठक का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख 26 राजनैतिक दलों का एक साथ एकत्रित होना इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता बदलाव के मूड में है तथा मोदी के कुशासन से मुक्ति चाहती है यह एकजुटता सिर्फ 26 राजनैतिक दलों की एकजुटता नहीं है यह देश की 65 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ढ्ढ..ह्न.ष्ठ.ढ्ढ.. की आवाज है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुशासन के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। आजादी के बाद पहली बार देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो देश के संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार कर रही है। 2024 के पहले होने वाले 5 राज्यों के 2023 के विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस विजयी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार विपक्षी दलों की निर्वाचित सरकारों को कमजोर करने का षड्यंत्र करती है देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करना भाजपा की मोदी सरकार का मूल चरित्र बन गया है। केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी सरकारों को अस्थिर करना धन, बल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर विपक्ष की सरकारों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका में जो हुआ था उससे देश का लोकतंत्र कलंकित हुआ है।

सरकार के खिलाफ 109 आरोप विधानसभा में पेश करेंगेः चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी पार्टी विधायक दल की बैठक भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुई। हमारे सभी विधायक उपस्थित थे और यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त तरीके से चर्चा की जाएगी। पिछली 30 तारीख को हमने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। करीब 109 बिंदुओं का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ तैयार है। आरोपपत्र के बिंदुओं पर आज विधायक दल की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सभी से विचार विमर्श के उपरांत 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है। हम कल विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा कराएं। पूरा समय देकर चर्चा कराएं और सभी तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ पूरा भाजपा विधायक दल और विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से घेरने का प्रयास करेंगे। भूपेश सरकार के असली चेहरे को इस प्रदेश की जनता के सामने उजागर करेंगे। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है, इस सरकार में तेजी के साथ भ्रष्टाचार बढ़ते गये। नए-नए घोटाले हुए हैं। 4 हजार करोड़ से ज्यादा का कोयला घोटाला, 2 हजार करोड़ रुपये का शराब घोटाला, रेत घोटाला,भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, जितनी भर्तियां हो रही है।

बस्तर के चार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुनः सक्रिय हो चुके दक्षिण पश्चिम मानसून से झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के लिए फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर के चार जिलों में जहां भारी से अतिभारी वर्षा की चेतावनी है तो वहीं पांच जिलों में भी इसी तरह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से जारी चेतावनी की माने तो आने वाले चौबीस घंटों के दौरान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव और कांकेर के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है और अधिकांश जिलों में रूक-रूककर बारिश होने का सिलसिला जारी है। रविवार और सोमवार देर शाम तक प्रदेश के बिल्हा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव जैसे इलाकों में लगातार बारिश होती रही है। वहीं मौसम विभाग ने अब आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता लगातार बढने् तथा अच्छी वर्षा का अनुमान जताया है।

बैरिकेड तोड़ कलेक्टर दफ्तर में घुसे भाजपाई

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला भाजपा के नेता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट दफ्तर तक गए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सभी कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे के केबिन में जा घुसे। अफसरों के साथ भाजपा के प्रदर्शनकारियों की बहस होती रही।भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और गौरी शंकर श्रीवास समेत तमाम नेताओं ने कलेक्टोरेट ऑफिस में हंगामा किया। सभी यहां नारेबाजी करने लगे। सिटी एसपी अभिषेक माहेश्वरी यहां फोर्स लेकर पहुंचे और नेताओं को रोका। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते अपराध को रोक पाने में नाकाम हैं। ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक सतनारायण शर्मा के खिलाफ भी भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को ये सभी नेता भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे। पहले से ही पुलिस की टीम ने कलेक्ट्रेट गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। मगर पुलिस का यह इंतजाम नाकाफी साबित हुआ। नेताओं ने बैरिकेड को तोड़ा और दफ्तर के भीतर हंगामा करने लगे।कलेक्टर से मिलकर इन नेताओं ने मांग करते हुए बताया कि रायपुर शहर के संतोषी नगर,बिरगांव, मुजगहन जैसे इलाकों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अवैध शराब के कारोबार, जमीन पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। इन इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया जाना चाहिए।

नाबार्ड ने मनाया स्थापना दिवस : बैजनाथ चन्द्राकर

रायपुर। नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में आज 42 वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने कहा कि कोआपरेटिव्ह बैंकों तथा सहकारी सोसाइटी के लिए नाबार्ड की भूमिका संरक्षक की तरह होती है। उन्होंने अवगत कराया गया कि नवा रायपुर में अपेक्स बैंक द्वारा अत्याधुनिक नवीन ट्रेनिंग सेंटर खोली जाएगी।श्री चन्द्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप सहकारी बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएं खोलने हेतु नाबार्ड तथा आरबीआई स्तर पर समुचित पहल किये जाने पर जोर दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पहल पर सहकारी क्षेत्र में अमूल परिवर्तन हुआ है। 725 नवीन सोसाइटीज़ का गठन करते हुए कुल राशि 185 करोड़ गोदाम सह-कार्यालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के 2058 सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, कृषि आदान सामग्री का वितरण आदि कार्य किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में सोसाइटीज़ आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ ज्ञानेंद्र मणि ने सहकारी बैंकों की सतत मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता की मजबूती के लिए हमें और अधिक कार्य करना है।

पारदर्शी चुनाव कराने रिटर्निंग अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की आज शुरूआत हुई. छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले, भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सलाहकार केएल विलफ्रेड और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टीसी महावर की मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ.सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि राज्य में

पारदर्शी, विवादरहित, त्रुटिरहित और समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए चार दिनों का यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागी भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स से चर्चा कर आम निर्वाचन और अपने दायित्वों से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं.

सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स 18 जुलाई से 21 जुलाई तक सभी जिलों के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को विधानसभा आम निर्वाचन की बारीकियों की जानकारी देंगे. नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स उन्हें निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं, कानूनों और गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे.

विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव से मिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 01 के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) श्री टी एस सिंहदेव से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की गई। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मांगों सहित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री टी एस सिंह देव द्वारा सकारात्मक पहल की बात कहीं गई। उन्होंने संगठन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा नहीं की जाएगी और सभी मांगों पर उचित निर्णय हेतु संबंधित अधिकारियों को शीघ्र दिशा निर्देश दिए जायेंगे।' श्री सिंहदेव ने आश्वासन दिया कि 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली,संविदा लाइन परिचारक कर्मचारियों का नियमितीकरण, 3 प्रतिशत तकनीकी भत्ता, रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, कैशलैस चिकित्सा आदि मांगों पर कंपनी के संचालक मंडल को शीघ्र निर्णय लिए जाने बाबत निर्देश दिया जाएगा।''फेडरेशन 01के संरक्षक श्री प्रीतम जैन, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, महासचिव आर सी चेट्टी के नेतृत्व में 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने मंत्री जी के निवास पर उनका स्वागत कर कर्मचारियों से संबंधित मांगो का ज्ञापन दिया। महासचिव आर सी चेट्टी ने कंपनी की राष्ट्रीय स्तर पर हर क्षेत्र में अग्रणी होने की बात बताते हुए उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, कर्मचारियों की कमी की स्थिति से भी उन्हें अवगत कराया, मंत्री जी ने संगठन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि संगठन के मांगों पर सकारात्मक निर्णय हेतु कंपनी के अध्यक्ष व संचालक मंडल को संगठन प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता रखने शीघ्र निर्देश देंगे।''महासचिव ने कांग्रेस शासित राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में बिजली कंपनी के कर्मियों के लिए किए गए पुरानी पेंशन की बहाली से अवगत कराते हुए मंत्री जी से निवेदन किया कि संगठन के उपरोक्त मांगों पर 15 अगस्त 2023 के पूर्व सकारात्मक निर्णय हेतु आपकी निश्चित पहल होगी,संगठन की ओर से कोरबा पूर्व शाखा अध्यक्ष श्री पवन दास ने आभार व्यक्त किया।''संगठन प्रतिनिधिमंडल में सर्व श्री प्रीतम जैन, सुरेंद्र शुक्ला,आर सी चेट्टी,आर के पटेल, सरोज राठौर, पवन दास,घनश्याम साहू,मनोज वर्मा, बलजीत कंवर,नागेंद्र नायक, सुरेश ठाकुर, नरेश शर्मा,यशवंत ठाकुर,राजेश खरे उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001